



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रधिकृत से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]  
No. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 1995/फाल्गुन 20, 1916  
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1995/PHALGUNA 20, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)  
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

का. धा. 610.—केन्द्रीय सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं. 2/1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के निम्नलिखित आपराधिक मामलों की पैरवी के लिए एतद्वारा श्री ए. पी. सिंह, एडवोकेट, जयपुर को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

- (1) आर.सी. 5/88- भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से संबंधित विशेष मजिस्ट्रेट/ए. सी. जे. एम./विशेष पुलिस स्थापना मामले, जयपुर की अदालत में एक मामला तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक अन्य मामला जिसका विशेष न्यायाधीश

- (2) आर.सी. 6/88- ए. सी. यू. (v)

- (3) आर. सी. 2/88- ए.सी. यू. (vii)

- (4) आर. सी. 3/88- ए. सी. यू. (vii)

(आवश्यक वस्तु अधिनियम मामले) जयपुर की अदालत में स्थानांतरित होने की संभावना है।

भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से संबंधित विशेष मजिस्ट्रेट/ए. सी. जे. एम./विशेष पुलिस स्थापना मामले, जयपुर की अदालत में एक मामला तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामलों के लिए), जयपुर की अदालत में एक अन्य मामला।

—यथोपरि—

—यथोपरि—

- (5) भार. सी. 1/88- विशेष न्यायाधीश (आवश्यक ए. सी. यू. (vii) वस्तु अधिनियम मामलों के लिए), जयपुर की अदालत में एक मामला तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के लिए भी ।

[सं. 225/30/94-ए. वी. डी.-II]

एस. सौंदर राजन, भवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 17th February, 1995

S.O. 610.—In exercise of the powers conferred by Section 24(B) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri A. P. Singh, Advocate, Jaipur as Special Public Prosecutor for conducting the criminal cases of Delhi Special Police Establishment as detailed below :—

- (1) RC. 5/88-ACU(V).—One Court case in the Court of Spl. Magistrate/ACJM/SPE cases Jaipur, for Indian Penal Code offences and another case under Essential Commodities Act likely to be transferred to the Court of Special Judge (for Essential Commodities Act cases) Jaipur.
- (2) RC. 6/88-ACU(V).—One Court case in the Court of Special Magistrate/ACJM/SPE cases Jaipur for Indian Penal Code offences and another court case in the court of Special Judge (for Essential Commodities Act cases) Jaipur under Essential Commodities Act.
- (3) RC. 2/88-ACU(VII).—As above.
- (4) RC. 3/88-ACU(VII).—As above.
- (5) RC. 1/88-ACU(VII).—Court case in the Court of Special Judge (for Essential Commodities Act cases) Jaipur and also for Indian Penal Code of offences.

[No. 225/30/94-AVD.II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

का. प्रा. 611.—केन्द्रीय सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं. 2/74) की धारा 24(8) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के निम्नलिखित आपराधिक मामलों की पैरवी के लिए एतद्वारा श्री भार. के. यादव, एडवोकेट, जयपुर की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

- (1) भार. सी. 2/88- आवश्यक वस्तु अधिनियम के ए. सी. यू. (iv) अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामलों के लिए), जयपुर की अदालत में एक मामला और भारतीय दण्ड संहिता अपराधों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट/ए. सी. जे. एम./ विशेष पुलिस

स्थापना मामले जयपुर की अदालत में एक अन्य मामला ।

- (2) भार. सी. 3/88- —यथोपरि—  
ए. सी. यू. (iv)
- (3) भार. सी. 4/88- —यथोपरि—  
ए. सी. यू. (iv)
- (4) भार. सी. 4/88- —यथोपरि—  
ए. सी. यू. (vi)
- (5) भार. सी. 6/88- —यथोपरि—  
ए. सी. यू. (vi)

[संख्या-225/30/94-ए. वी. डी.-II]

एस. सौंदर राजन, भवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 1995

S.O. 611.—In exercise of the powers conferred by Section 24(8) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri R.K. Yadav, Advocate Jaipur as Special Public Prosecutor for conducting criminal cases of Delhi Special Police Establishment as detailed below :—

- (1) RC. No. 2/88-ACU(IV).—One court case in the court of Special Judge (for Essential Commodities Act cases) Jaipur under Essential Commodities Act and another court case, in the court of Special Magistrate/ACJM/SPE cases Jaipur for Indian Penal Code offences.
- (2) RC. 3/88-ACU(IV).—As above.
- (3) RC. 4/88-ACU (IV).—As above.
- (4) RC. 4/88-ACU(VI).—As above.
- (5) RC. 6/88-ACU(VI).—As above.

[No. 225/30/94-AVD.II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(समाहर्ता का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

कानपुर, 12 दिसम्बर, 1994

सीमा शुल्क

का. प्रा. 612. —सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 152 के खण्ड (ए) के अधीन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 33/94-कस (एन टी) दिनांक 01 जुलाई, 1994 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी में, एम. सी. कौल, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानपुर एतद्वारा, ग्राम छाता, दिल्ली-मथुरा रोड पर 110 कि.मी. का शिला खण्ड (पत्थर) तहसील छाता, जनपद-मथुरा उ. प्र. में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की

धारा 9 के अन्तर्गत 100% ई. ओ. यू. व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक माल गोदाम स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

[सं. 03/94-कस्टम्स (एनटी)/फा. सं. VIII(40)  
144-कस्ट/डस्ट्यू एच/94/23437]

एम. सी. कौल, समाह्वत

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Office of the Collector Central Excise)

Kanpur, the 12th December, 1994

## CUSTOMS

S.O. 612.—In exercise of the power delegated to the undersigned vide Notification No. 33/94-CUS(NT), Dated the 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I, M.C. Kaul, Collector of Customs & Central Excise, Kanpur hereby declare village Chhata, 110 k.m. Stone, Delhi Mathura Road, Tehsil Chhata, Distt. Mathura, U.P. to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the purposes of setting up of 100 per cent E.O.U.

[No. 03/94-CUSTOMS(NT).F. No. VIII(40)144-CUST/WH/94/2670]

M. C. KAUL, Collector

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1995

## स्टाम्प

का. भा. 613. —भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भागे उस शुल्क को माफ करती है जो कि विद्युत वित्त निगम लिमि. द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र एक सौ पचास करोड़ रुपये के मूल्य के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप में वर्णित 17% पी. एफ. सी. (पहली श्रृंखला) के सुरक्षित विमोच्य बांडों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी है।

[सं. 1/95-स्टाम्प-का. सं. 33/6/94-वि. क.]

आत्मा राम, भवर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 18th January, 1995

## STAMPS

S.O. 613.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby further remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes—described as 17 per cent P.F.C. Bonds (1st Series) secured redeemable of the value of rupees One fifty crores only to be issued by Power Finance Corporation Ltd. are chargeable under the said Act.

[No. 1/95-Stamps F. No. 33/6/94-ST]  
ATMA RAM, Under Secy

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का. भा. 614. —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. मंडल कार्यालय, भागलपुर
2. शाखा कार्यालय, भररिया
3. शाखा कार्यालय बेगूसराय
4. शाखा कार्यालय-1, भागलपुर
5. शाखा कार्यालय-2, भागलपुर
6. शाखा कार्यालय, देवघर
7. शाखा कार्यालय, दुमका
8. शाखा कार्यालय, फारबिसगंज
9. शाखा कार्यालय, गोड्डा
10. शाखा कार्यालय, गुलाबबाग
11. शाखा कार्यालय, जमुई
12. शाखा कार्यालय, कटिहार
13. शाखा कार्यालय खगडिया
14. शाखा कार्यालय, किशनगंज
15. शाखा कार्यालय लखीसराय
16. शाखा कार्यालय, मधेपुरा
17. शाखा कार्यालय, मुंगेर
18. शाखा कार्यालय, पूर्णिया
19. शाखा कार्यालय, सहरसा
20. शाखा कार्यालय, साहिबगंज
21. शाखा कार्यालय, सुपौल
22. मण्डल कार्यालय, ठाणे
23. शाखा कार्यालय-91जे, ठाणे
24. शाखा कार्यालय-933, ठाणे
25. शाखा कार्यालय-41 जी, डाबिवली
26. शाखा कार्यालय-91 एम, मिर्बडी
27. शाखा कार्यालय-92ए, वाशी
28. शाखा कार्यालय-92 बी, अंबरनाथ
29. शाखा कार्यालय-92 सी, कल्याण
30. शाखा कार्यालय-92 टी, कल्याण
31. शाखा कार्यालय-92 एन, कोपरी
32. शाखा कार्यालय-92 के, खोपोली
33. शाखा कार्यालय 934, कल्याण
34. शाखा कार्यालय-936, पुणे

35. शाखा कार्यालय-932, उहणू
36. शाखा कार्यालय-92 एफ, उल्हास नगर
37. शाखा कार्यालय-92 जी, नालासोपारा
38. शाखा कार्यालय-92 जे, बोईसर
39. शाखा कार्यालय, भाईंदर
40. शाखा कार्यालय, रोहा
41. शाखा कार्यालय, 91 एन, वसई
42. शाखा कार्यालय-91 पी, पनवेल
43. शाखा कार्यालय-91 एच, महाड
44. वेतन बचत योजना शाखा, ठाणे
45. पेंशन एवं स्कीम शाखा, ठाणे
46. शाखा कार्यालय-917, उल्हासनगर

32. Branch Office-92 K, Khopoli
33. Branch Office-934, Kalyan
34. Branch Office-936, Pune
35. Branch Office-932, Dahanu
36. Branch Office-92 F, Ulhasnagar
37. Branch Office-92 G, Nalasaopara
38. Branch Office-92 J, Boisar
39. Branch Office, Bhaindar
40. Branch Office, Roha
41. Branch Office-91 N, Vasai
42. Branch Office-91 P, Panvel
43. Branch Office-91 H, Mahad
44. Pay Savings Scheme Branch, Thane
45. Pension & Scheme Branch, Thane
46. Branch Office-917, Ulhasnagar

[No. 11013/4/94-HIC]  
S. K. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

[सं. 11013/4/94—हि. का. क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 614.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Life Insurance Corporation of India, under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, where of more than 80 percent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. Divisional Office, Bhagalpur
2. Branch Office, Arariya
3. Branch Office, Begusarai
4. Branch Office-1, Bhagalpur
5. Branch Office-2, Bhagalpur
6. Branch Office, Devghar
7. Branch Office, Dumka
8. Branch Office, Farbisganj
9. Branch Office, Goida
10. Branch Office, Gulbbag
11. Branch Office, Jamul
12. Branch Office, Katihar
13. Branch Office, Khagariya
14. Branch Office, Kishanganj
15. Branch Office, Lakhisarai
16. Branch Office, Madhepura
17. Branch Office, Munger
18. Branch Office, Purnia
19. Branch Office, Shersa
20. Branch Office, Sahibganj
21. Branch Office, Supol
22. Divisional Office, Thane
23. Branch Office-91 J, Thane
24. Branch Office-933, Thane
25. Branch Office-91 G, Dabivall
26. Branch Office-91 M, Bhivandi
27. Branch Office-92 A, Vasi
28. Branch Office-92 B, Ambarnath
29. Branch Office-92 C, Kalva
30. Branch Office-92 D, Kalyan
31. Branch Office-92 H, Kopari

का. भा. 615.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित राष्ट्रीय बचत संगठन के निम्नलिखित कार्यालय को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. राष्ट्रीय बचत संगठन, पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

[सं. 11013/4/94—हि. का. क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 615.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the National Savings Organisation, under the Administrative control of Ministry of Finance Department of Economic Affairs, whereof more than 80 percent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. National Savings Organisation, Western Maharashtra Regional Office, Pune.

[No. 11013/4/94-HIC]

S. K. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का. भा. 616.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके

80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

कम्पनी का नाम : नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. मंडल कार्यालय, पालमपुर
2. मंडल कार्यालय-13, बम्बई
3. वर्धमान नगर शाखा कार्यालय, नागपुर
4. शाखा कार्यालय, वर्धा
5. शाखा कार्यालय, कामठी
6. शाखा कार्यालय, दुमका
7. मंडल कार्यालय, लहुराबीर, वाराणसी
8. शाखा कार्यालय-5, लखनऊ
9. डायरेक्ट एजेंट शाखा, लखनऊ
10. शाखा कार्यालय, बैदहन, जिला : सीधी (म. प्र.)
11. क्षेत्रीय कार्यालय-2, चण्डीगढ़

[सं. 11013/4/94-हि. का. क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 616.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976, Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India, under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : National Insurance Co. Ltd.

1. Divisional Office, Palampur
2. Divisional Office-13, Bombay
3. Vardhman City Branch Office, Nagpur
4. Branch Office, Vardha
5. Branch Office, Kamthi
6. Branch Office, Dumka
7. Divisional Office, Lahurabir, Varanasi
8. Branch Office-5, Lucknow
9. Direct Agent Branch, Lucknow
10. Branch Office, Baidhan, Dist. Sidhi (M.P.)
11. Regional Office-2, Chandigarh.

[No. 11013/4/94-HIC]

S. K. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का. भा. 617.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

कम्पनी का नाम : ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. शाखा कार्यालय, कलोल
2. शहर शाखा कार्यालय, मेहसाणा

3. मंडल कार्यालय, नडियाद
4. मंडल कार्यालय-1, बड़ौदा
5. शाखा कार्यालय, ईडर
6. शहर शाखा कार्यालय-6, अहमदाबाद
7. शाखा कार्यालय, अंकलेश्वर
8. शाखा कार्यालय, मोडासा
9. शाखा कार्यालय, गांधीधाम
10. मण्डल कार्यालय, भरुच
11. शाखा कार्यालय, वयारा
12. शहर शाखा कार्यालय-1, अहमदाबाद
13. शाखा कार्यालय, छानी

[सं. 11013/4/94-हि. का. क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 617.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India, under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, whereof more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : The Oriental Insurance Co. Ltd.

1. Branch Office, Kalol
2. City Branch Office, Mehsana
3. Divisional Office, Nadiad
4. Divisional Office-1, Baroda
5. Branch Office, Idar
6. City Branch Office-6, Ahmedabad
7. Branch Office, Ankaleshwar
8. Branch Office, Modasa
9. Branch Office, Gandhidham
10. Divisional Office, Bharuch
11. Branch Office, Vayara
12. City Branch Office-1, Ahmedabad
13. Branch Office, Chhani

[No. 11013/4/94-HIC]

S. K. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का. भा. 618.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

कम्पनी का नाम : बि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. शाखा कार्यालय, बिसे पाले

2. शाखा कार्यालय, दादर
3. मंडल कार्यालय, कलनी
4. मंडल कार्यालय तारदेव
5. मंडल कार्यालय, तारदेव ईकाई

[सं. 11013/4/94-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 618.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India, under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, whereof more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi. Name of the Company : The New India Assurance Co. Ltd.

1. Branch Office, Ville Parle
2. Branch Office, Dadar
3. Divisional Office, Kalina
4. Divisional Office, Tardev
5. Divisional Office, Tardev Ekai

[No. 11013/4/94-HIC]  
S. K. VERMA, Under Secy

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का. भा. 619.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 26 की उपधारा (1) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (गख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा अनुषंगी बैंक अधिकारी संघ, मंसूर एकक के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस. गुंडुराव (प्रबंधक) (लेखापरीक्षा निरीक्षण विभाग स्टेट बैंक आफ मंसूर, प्रधान कार्यालय, बंगलौर में कार्यरत) को स्टेट बैंक आफ मंसूर के उन कर्मचारियों में से, जो कर्मकार नहीं हैं, दिनांक 16 फरवरी, 1995 से 15 फरवरी, 1998 को समाप्त अवधि के लिए या जब तक वे स्टेट बैंक आफ मंसूर का अधिकारी पद छोड़ नहीं देते, इतमें से जो भी पहले हो, स्टेट बैंक आफ मंसूर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति करती है।

[संख्या 8/5/94 बी प्रो-I]

के के मंगल अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 619.—In pursuance of clause (cb) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (1) and sub-section (2A) of section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoint Shri S. Gundu Rao, presently Chairman of Associate Banks' Officers' Association—Mysore Unit [working as Manager (Audit), Inspection Department, State Bank of Mysore, Head Office, Bangalore], as a director on the Board of the State Bank

of Mysore, from among the employees of the State Bank of Mysore who are not workmen with effect from the 16th February, 1995 and upto 15th February, 1998, or until he ceases to be an officer of the State Bank of Mysore whichever is earlier.

[No. 8/5/94-BO. I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1995

का. भा. 620.—बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध पंजाब नेशनल बैंक पर 31, मार्च, 1995 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखाओं और तुलनपत्र को निर्धारित ढंग से प्रकाशित करने और उसकी तीन प्रतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितम्बर, 1994 तक की बढ़ाई हुई अवधि के अन्दर-अन्दर विवरणियों के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[सं 12/9/93-बी प्रो ए]

बी. एल. सचदेव, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd February, 1995

S.O. 620.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank upto 31st March, 1995 in so far as it is required to publish the accounts and balance sheet as at 31st March, 1994 together with auditors' report in the prescribed manner and submit three copies thereof as returns to the Reserve Bank of India within the extended period upto 30th September, 1994.

[No. 12/9/93-ROA]

B. L. SACHDEVA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

बंबई, 31 जनवरी, 1995

का. भा. 621.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 18 और धारा 73 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उस व्यक्ति को छोड़कर जो प्रदर्शनी/व्यापार मेला में भाग लेने के लिए भारत के बाहर हो, भारत के निवासी व्यक्ति को भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा का खाता खोलने और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेला में प्रदर्शन सह विक्री हेतु निर्यातित आभूषण और धन्य माल की विक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा

जमा करने के लिए उसका परिचालन करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि प्रदर्शनी/व्यापार मेला खत्म होने के तुरंत बाद खाता बंद कर दिया जाए और प्रदर्शनी/व्यापार मेला की समाप्ति के समय विदेशी मुद्रा में राशि प्रत्यावर्तित की जाए तथा निर्यातक उसके बैंकर द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित कारोबार और प्रदर्शनी/व्यापार मेला में प्रदर्शन-सह बिक्री के लिए निर्यातित माल की बिक्री का पूरा हिसाब और शेष आभूषण/माल के पुनर्आयात का साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक को 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करे।

[अधिसूचना सं. फेरा 161/95/आरबी]

डी. आर. मेहता, उप गवर्नर

# RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Bombay, the 31st January, 1995

S.O. 621.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 8 read with Section 18 and sub-section (3) of Section 73 of the Foreign Exchange Regional Act, 1973 (46 of 1973), the Reserve Bank of India hereby permits a person resident in India but who is out of India for participation in exhibition/trade fair to open with a bank outside India an account in foreign currency and operate for depositing the foreign exchange obtained by sale of jewellery and other goods exported for display-cum-sale in the international exhibition/trade fair provided that the account is closed immediately after close of exhibition/trade fair and the amount is repatriated in foreign exchange at the time of closure of the exhibition/fair and the exporter furnishes to Reserve Bank the full account of transactions and sale of goods exported for display-cum-sale in exhibition/trade fair duly certified by his banker and evidence of reimport of balance jewellery/goods within a period of 15 days.

[Notification No. F.E.R.A. 161/95/RB]

D. R. MEHTA, Dy. Governor

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का. आ. 622.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभि-प्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जत और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आणय की सूचना देती है,

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई)/III/जी.आर. 546—294, तारीख 8 फरवरी, 1994 का निरीक्षण वैम्स्टर्न कोलफील्ड्स लि., (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कलकट्टा छिदवाड़ा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भार साधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व) वैम्स्टर्न कोलफील्ड्स लि., कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) को भेजेंगे।

## अनुसूची

ब्लॉक 1

सेथिया ब्लॉक 1 और 2

पंच क्षेत्र

जिला—छिदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

[प्लॉट सं. सी—1 (ई)/III/जी. आर./546—294, तारीख 8 फरवरी, 1994]

क्र. क्रम का नाम संख्या	पटवारी सॉकिल सं.	बन्दीबस्त सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सेथिया	72	583	परासिया	छिदवाड़ा	2800	भाग
2. छिदवाड़ी	70	266	परासिया	छिदवाड़ा	4055	भाग

कुल क्षेत्र 6.855 हेक्टेयर (लगभग)  
या 16.940 एकड़ (लगभग)

## सीमा वर्णन

- झ—ञ— रेखा बिन्दु "झ" से प्रारम्भ होती है और पेंच नदी के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ दिघावनी ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु "अ" पर मिलती है।
- अ—ट रेखा ग्राम दिघावनी से होकर जाती है, पेंच नदी पार करती है और ग्राम सेधिया से होकर प्रागे बढ़ती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है।
- ट—ड रेखा पेंच नदी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ ग्राम सेधिया से होकर जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड—ड— रेखा ग्राम सेधिया और छिदा की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है, पेंच नदी पार करती है और बिन्दु "ड" पर पेंच नदी के मध्य में मिलती है।
- ड—ड—रेखा पेंच नदी के मध्य से होकर ग्राम छिदा और दिघवनी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड—झ—रेखा ग्राम दिघवनी से होकर गुजरती है, पेंच नदी पार करती है और प्रारम्भिक बिन्दु "झ" पर मिलती है।

अनुसूची ब्लॉक 2

सेधिया ब्लॉक 1 और 2

पेंच क्षेत्र

जिला छिदावाड़ा (मध्य प्रदेश)

[प्लान नं. सी/1 (ई) III/जी प्रार/546-294, तारीख 8 फरवरी, 1994]

क्रम संख्यांक	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	बन्दोबस्त सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	सेधिया	72	583	परासिया	छिदावाड़ा	5.079	भाग
				कुल क्षेत्र		5.079 हेक्टर (लगभग) या 12.550 एकड़ (लगभग)	

## सीमा वर्णन :—

क—ख—ग—घ—ङ—च— रेखा बिन्दु "क" से प्रारम्भ होती है और ग्राम सेधिया से होकर जाती है तथा बिन्दु "च" पर मिलती है।

च—छ—ज—क :—रेखा सेधिया विवृत्त खान की विद्यमान पट्टाधृति सीमा के साथ-साथ ग्राम सेधिया से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/12/94/94 एल एस डब्ल्यू]

नरेन्द्र भगत, निदेशक

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 622.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(EIII)/GR/546-294 dated the 8th February, 1994 of the area covered by this notification can be inspected in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines Nagpur-440001 (Maharashtra) or in the office of the Collector Chhindwara, (Madhya Pradesh) or in the office of the coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Officer-in-Charge and of the Department (Revenue), Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE BLOCK-I  
SETHIA BLOCK I AND II  
PENCH AREA

## DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH)

(Plan No. C-1(E) III/GR/546-294 dated the 8th February, 1994)

Sl. No.	Name of Village	Patwari circle number	Settlement number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Sethia	72	583	Parasia	Chhindwara	2.800	Part
2.	Dighawani	70	266	Parasia	Chhindwara	4.055	Part
Total area :						6.855 Hectares (approximately) or 16.940 acres (approximately)	



## Boundary description :

- I-J Line starts from point 'I' and passes through village Dighawani along the Western Bank of Pench River and meets at point 'J'.
- J-K Line passes through village Dighawani, crosses Pench River and proceeds through village Sethia and meets at point 'K'.
- K-L Line passes through village Sethia along the Eastern bank of Pench River and meets at point 'L'.

L-M Line passes along the common village boundary of villages Sethia and Chhinda, crosses Pench River and meets at the centre of Pench River at point 'M'.

M-N Line passes along the common village boundary of villages Chhinda and Dighawani through the centre of Pench River and meets at point 'N'.

N-I Line passes through village Dighawani, crosses Pench River and meets at starting point 'I'.

**SCHEDULE BLOCK-II  
SETHIA BLOCK I AND II  
PENCH AREA**

**DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH)**  
(Plan No. C-I (E)III/GR/346-294 dated the 8th February, 1994)

Sl. No.	Name of village	Patwari circle Number	Settlement number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Sethia	72	583	Parasia	Chhindwara	5.079	Part
Total area :						5.079 hectares (approximately)	
						or 12.550 acres (approximately)	
Total area of Block-I and Block-II			— 11.934 hectares (approximately)				
			or 29.490 acres (approximately)				

## Boundary description :

- A-B-C-D-E-F Line starts from point 'A' and passes through village Sethia and meets at point 'F'.
- F-G-H-A Line passes through village Sethia along the existing lease hold boundary of Sethia opencast mine and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/12/94-LSW]  
N. BHAGAT, Director

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995  
शुद्धि पत्र

338 पर प्रकाशित भारत के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 337, दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 में:—  
पृष्ठ 336 पर

अनुसूची में "माटरी ब्लॉक कैंहान क्षेत्र" के स्थान पर "माटरी ब्लॉक कन्हान क्षेत्र" पढ़िए।

[फा. सं. 43015/9/92-एल एस डब्ल्यू]

का. आ. 623.—भारत के राजपत्र भाग-II खंड 3, उपखंड  
(ii) तारीख 29 जनवरी, 1994 के पृष्ठ 336 से

नरेन्द्र भगत, निदेशक

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का. आ. 624—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. 22652, तारीख 13-9-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा।

बाद- अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र हेक्टर	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	मथुरा	मथुरा	सोन	924	0.0400	
				918	0.2340	
				920	0.0100	
				919	0.0360	
				921	0.0080	
				922	0.0040	
				923	0.0940	
				916	0.0060	
				899	0.3420	
				900	0.0300	
				902	0.3600	
				883	0.0060	
				882	0.1310	
				881	0.0110	
				879	0.0420	
				863	0.0240	
				861	0.0900	
				862	0.1880	
				860	0.0060	
				864	0.0840	
				859	0.3900	
				711	0.0360	
				712	0.3900	
				717	0.0080	
				718	0.0040	
				735	0.0530	
				729	0.4600	
				728	0.1020	
				725	0.1080	
				726	0.2170	
				445	0.0300	
				468	0.1020	
				467	0.0960	
				466	0.3500	
				461	0.1320	
				459	0.0180	
				458	0.1750	
				457	0.0300	
				456	0.1900	
				454	0.0190	
				453	0.1350	

1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	मथुरा	मथुरा	सीत	452	0.0030	
				451	0.0020	
				433	0.0120	
				432	0.0030	
				430	0.7000	
				384	0.0700	
				408	0.0030	
				352	0.0100	
				351	0.0900	
				348	0.0030	
				347	0.0060	
				346	0.0050	
				345	0.0850	
				344	0.1270	
				342	0.2860	
				343	0.0600	
				339	0.0040	
				338	0.2800	
				336	0.1480	
				335	0.1900	
				334	0.1300	
				244	0.0100	
				240	0.1660	
				241	0.0600	
				239	0.0550	
				238	0.3800	
				237	00.020	
				236	0.0040	
				234	0.0120	
सम्पूर्ण योग				70	7.6970	हेक्टेयर
या				19.011	एकड़	
या				30-08-07	बीघा	

[सं. एल. 14016/3/94 जी. पी.]

अर्थेन्दु सेन, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 624.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2265 dated 13-9-94 under sub-section (1) of section (3) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User) in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Hectare	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Mathura	Mathura	Son	924	0.0400	
				918	0.2340	
				920	0.0100	
				919	0.0360	
				921	0.0080	
				922	0.0040	
				923	0.0940	
				916	0.0060	
				899	0.3420	
				900	0.0300	
				902	0.3600	
				883	0.0060	
				882	0.1310	
				881	0.0110	
				879	0.0420	
				863	0.0240	
				861	0.0900	
				862	0.1880	
				860	0.0060	
				864	0.0840	
				859	0.3900	
				711	0.0360	
				712	0.3900	
				717	0.0080	
				718	0.0040	
				735	0.0530	
				729	0.4600	
				728	0.1020	
				725	0.1080	
				726	0.2170	
				445	0.0300	
				468	0.1020	
				467	0.0960	
				466	0.3500	
				461	0.1320	
				459	0.0180	
				458	0.1750	
				457	0.0300	
				456	0.1900	
				454	0.0190	
				453	0.1350	
				452	0.0030	
				451	0.0020	
				433	0.0120	
				432	0.0030	
				430	0.7000	
				384	0.0700	
				408	0.0030	
				352	0.0100	

1	2	3	4	5	6	7
			Son	351	0.0900	
				348	0.0030	
				347	0.0060	
				346	0.0050	
				345	0.0850	
				344	0.1270	
				342	0.2860	
				343	0.0600	
				339	0.0040	
				338	0.2800	
				336	0.1400	
				335	0.1900	
				334	0.1300	
				244	0.0100	
				240	0.1660	
				241	0.0600	
				239	0.0550	
				238	0.3800	
				237	0.0020	
				236	0.0040	
				234	0.0120	
G. TOTAL				70	7.6970 Hectare	
				OR	19.011 Acres	
				OR	30-08-07 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 625:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का, आ.सं. 1283 तारीख 4-6-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय प्रकट कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## वाद-अनुसूची

## एच.बी.जे. अपप्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. हेक्ट.	अन्य विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
मथुरा	छाता	छाता	कौकेरा	114	0.0300					
				79	0.1320					
				80	0.5880					
				81	0.2220					
				77	0.0060					
				45	0.2260					
				44	0.0180					
				46	0.2480					
				42	0.0080					
				48	0.0400					
				33	0.0420					
				32	0.1500					
				31	0.0350					
				35	0.1880					
				36	0.2200					
				29	0.0090					
				20	0.6540					
				19	0.2160					
				22	0.0150					
				योग				19	3.0470	हेक्टेअर
								या	7.526	एकड़
								या	12-00-16	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 625.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1283 dated 4-6-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Kaunkera	114	0.0300	
				79	0.1320	
				80	0.5880	
				81	0.2220	
				77	0.0060	
				45	0.2260	
				44	0.0180	
				46	0.2480	
				42	0.0080	
				48	0.0400	
				33	0.0420	
				32	0.1500	
				31	0.0350	
				35	0.1880	
				36	0.2200	
				29	0.0090	
				20	0.6540	
				19	0.2160	
				22	0.0150	
				TOTAL	19	3.0470 Hectares
				OR	7.526 Acres	
				OR	12-00-16 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 626:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. तारीख 1626/16-7-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अवॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

बाव-अनसूची

एच.बी. जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हेक्टे.	अन्य विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
मथुरा	छाता	छाता	घनीटा	84	0.0160					
				91	0.8780					
				100	0.0030					
				106	0.2780					
				107	0.2480					
				108	0.0030					
				109	0.0080					
				110	0.2900					
				111	0.2480					
				113	0.0330					
				114	0.0980					
				112	0.1780					
				115	0.0030					
				120	0.0080					
				121	0.2950					
				122	0.0080					
				128	0.0030					
				130	0.2980					
				31	0.0080					
				24	0.3180					
				25	0.1640					
				26	0.0820					
				160	0.5330					
				157	0.0030					
				156	0.6830					
				155	0.1180					
				154	0.0630					
				153	0.0160					
				योग				28	4.8840	हेक्टेअर
								या	12-064	एकड़
								या	19-06-02	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक



New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 626.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1626 dated 16-7-1994, under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of the declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

### CASE SCHEDULE H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks				
1	2	3	4	5	6	7				
Mathura	Chhata	Chhata	Dhanauta	84	0.0160					
				91	0.8780					
				100	0.0030					
				106	0.2780					
				107	0.2480					
				108	0.0030					
				109	0.0080					
				110	0.2900					
				111	0.2480					
				113	0.0330					
				114	0.0980					
				115	0.0030					
				112	0.1780					
				120	0.0080					
				121	0.2950					
				122	0.0080					
				128	0.0030					
				130	0.2980					
				31	0.0080					
				24	0.3180					
				25	0.1640					
				26	0.0820					
				160	0.5330					
				156	0.6830					
				157	0.0030					
				155	0.1180					
				154	0.0630					
				153	0.0160					
				TOTAL				28	4.8840 Hectares	
								OR	12-064 Acres	
								OR	19-06-02 Bigha	

[No. L. 14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का. आ. 627 :- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ. सं. 2667 तारीख 8-10-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः संक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों का उपयोग में अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## बाद-अनुसूची

एच.बी.जे. अपप्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र बीघा/एकड़/हेक्टर	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	छाता	छाता	अजनोटी	153	0.3940	
				152	0.0060	
				145	0.4560	
				144	0.0060	
				143	0.1160	
				योग	5 0.9780	हेक्टेअर
				या	2.415	एकड़
				या	03-17-06	बीघा

[सं. एन-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 627.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2667 dated 8-10-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Ajnothi	153	0.3940	
				152	0.0060	
				145	0.4560	
				144	0.0060	
				143	0.1160	
				TOTAL	5	0.9780 Hectares
				OR	2.416 Acres	
				OR	03-7-6 Bigha	

[N. L. 42, 6/3/94—G.P.]

AR. JEN. C. EN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का. आ. 628 :- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अवन) अधिनियम, 1992 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ.सं. 1278 तारीख 4-6-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## बाद-अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हिक्टा.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	छाता	छाता	सुजावली	89	0.5860	
				90-ब	0.4190	
				88	0.1830	
				86	0.3860	
				82	0.2680	
				83	0.1080	
				76	0.0080	
				69-ब	0.1470	
				70	0.3920	
				71	0.0900	
				72	0.6880	
				73	0.0080	
				2	0.2940	
				1	0.4180	
				कुल योग 14	3.9930	हेक्टेयर
				या	9.862	एकड़
				या	15-15-12	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्थेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 628.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1278 dated 4-6-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Sujaoli	89	0.5860	
				90B	0.4190	
				88	0.1830	
				86	0.3860	
				82	0.2680	
				83	0.1080	
				76	0.0080	
				69B	0.1470	
				70	0.3920	
				71	0.0900	
				72	0.6880	
				73	0.0080	
				2	0.2940	
				1	0.4180	
				G. TOTAL		
			OR	9.802	Acres	
			OR	15-15-12	Bigha	

[No L-14016/3/94-G P]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का. आ. 629 :- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. तारीख 1622/16-8-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

वाढ-अनुसूची  
एच.बी.जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र बीघा/एकड़/हेक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	छाता	छाता	बरचावली	580	0.0440	
				579	0.6140	
				578	0.0060	
				578/692	0.0320	
				570	0.310	
				योग 5	0.7270	हेक्टेअर
				या	1.795 एकड़	
				या	02-17-09 बीघा	

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 629.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1622 dated 16-7-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority was under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

CASE SCHEDULE  
H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Barchawali	580	0.0440	
				579	0.6140	
				578	0.0060	
				578/692	0.0320	
				570	0.0310	
				TOTAL		5
		OR	1.795 Acres			
		OR	02-17-09 Bigha			

[No L-14016/3/94-G P]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 630.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. 1619 तारीख 16-7-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## बाद-अनुसूची

## एच.बी.जे. अपप्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र (हेक्ट०)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भथुरा	छाता	छाता	शाहपुर	555	0.0240	
				557	0.3220	
				562	0.0300	
				558	0.0356	
				564	0.2500	
				584	0.2620	
				585	0.1360	
				586	0.0690	
				587	0.0030	
				593	0.0588	
				592	0.0036	
				594	0.4540	
				596	0.1840	
				548	0.1600	
				544	0.2700	
				545	0.4104	
				599	0.0156	
				546	0.0060	
				547	0.0480	
				268	0.6380	
				269	0.1920	
				263	0.1440	
				267	0.0240	
				265	0.1570	
				264	0.0024	
				266	0.3700	

1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	छाता	छाता	शाहपुर (जार)	1162/264	0.0846	
				259	0.0240	
				चकरोड़	0.0360	
				252	0.1920	
				251	0.4320	
				250	0.1530	
				249	0.7390	
				245	0.0060	
				246	0.0360	
				230	0.2160	
				चकरोड़	0.0180	
				108	0.1200	
				चकरोड़	0.0300	
				110	0.1630	
				109	0.1800	
				103	0.0120	
				99	0.0120	
				100	0.2430	
				101	0.4080	
				102	0.1628	
				92	0.0300	
कुल योग				47	7.5548	हैक्टेयर
				या	18.66	एकड़
				या	29-17-03	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 630.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1619 dated 16-7-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Shahpur	555	0.0240	
				557	0.3220	
				562	0.0300	



1	2	3	4	5	6	7
Mathura	Chhata	Chhata	Shahpur [contd.]	558	0.0356	
				564	0.2500	
				584	0.2620	
				585	0.1360	
				586	0.0690	
				587	0.0030	
				593	0.0588	
				592	0.0036	
				594	0.4540	
				596	0.1840	
				548	0.1600	
				544	0.2700	
				545	0.4104	
				599	0.0156	
				546	0.0060	
				547	0.0480	
				268	0.6380	
				269	0.1920	
				263	0.1440	
				267	0.0240	
				265	0.1570	
				264	0.0024	
				266	0.3700	
				1162/264	0.0846	
				259	0.0240	
			Chakroad		0.0360	
				252	0.1920	
				251	0.4320	
				250	0.1530	
				249	0.7390	
				245	0.0060	
				246	0.0360	
				230	0.2160	
			Chakroad		0.0180	
				108	0.1200	
			Chakroad		0.0300	
				110	0.1630	
				109	0.1800	
				103	0.0120	
				99	0.0120	
				100	0.2430	
				101	0.4080	
				102	0.1628	
				92	0.0300	
G. TOTAL				47	7.5548 Hectares	
				OR	18.66 Acres	
				OR	29-17-03 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 631.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. 1270 तारीख 18-5-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग को अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### बाद अनुसूची

एच.बी.जे. अप-ग्रेडेशन गैस पाइप लाइन परियोजना

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्र हेक्टेयर में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	दनकौर	बिसायब	219	0.0120	
				198	0.2020	
				196	0.0720	
				195	0.0840	
				201	0.0060	
				176	0.2612	
				202	0.0588	
				175	0.1188	
				150	0.0180	
				151	0.1200	
				144	0.0180	
				137	0.1120	
				138	0.0060	
				148	0.0300	
				141	0.2435	
				121	0.0030	
				120	0.2600	
				119	0.0060	
				33	0.0030	
				31	0.2020	
				22	0.0060	
				19	0.0090	
				18	0.3430	
				11	0.0040	
				12	0.0060	

1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	दन्कौर	बिसायच	10	0.0640	
				9	0.1000	
				8	0.0060	
				7	0.0030	
				2	0.2845	
				3	0.1755	
संपूर्ण योग				31	2.8373	हेक्टेयर
				या	6.998	एकड़
				या	11-03-18	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अन्वेषण सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 631.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1270, dated 18-5-94 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UP-GRADATION GAS PIPE LINE PROJECT

Distt.	Tehsil	Paragna	Village	Plot No.	Acquired Area in Hectare	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Bulandshaher	Sikandrabad	Dankaur	Bisaich	219	0.0120	
				198	0.2020	
				196	0.0720	
				195	0.0840	
				201	0.0060	
				176	0.2612	
				202	0.0588	
				175	0.1188	
				150	0.0180	
				151	0.1200	
				144	0.0180	
				137	0.1120	
				138	0.0060	
				148	0.0300	
				141	0.2435	

1	2	3	4	5	6	7
Buland Shaher	Sikandrabad	Dunkaur	Biraich	121	0.0030	
				120	0.2600	
				119	0.0060	
				33	0.0030	
				31	0.2020	
				22	0.0060	
				19	0.0090	
				18	0.3430	
				11	0.0040	
				12	0.0060	
				10	0.0640	
				9	0.1000	
				8	0.0060	
				7	0.0030	
				2	0.2845	
				3	0.1755	
TOTAL				31	2.8373 Hectare	
				OR	6.998 Acres	
				OR	11-03-18 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 632.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ. सं. 1275 तारीख 18-5-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अयॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

वाद-अनुसूची

एच.बी.जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र बीघा/एकड़/हेक्टर	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	दनकौर	लड़पुरा	604	0.0560	
				546	0.0680	
				550	0.0880	

1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	दनकौर	लड़पुरा	549	0.0496	
				548	0.0904	
				543	0.1000	
				527	0.1460	
				528	0.1800	
				531	0.0640	
				530	0.0080	
				529	0.1630	
				525	0.0080	
				524	0.0880	
				523	0.0060	
				520	0.2360	
				519	0.0260	
				518	0.0192	
				488	0.0060	
				419	0.0760	
				435	0.0580	
				420	0.1980	
				421	0.1190	
				427	0.1610	
				429	0.0198	
				430	0.0030	
				428	0.0420	
				410	0.0590	
				409	0.0680	
				408	0.0210	
				407	0.0340	
				348	0.1280	
				349	0.0616	
				134	0.0520	
				352	0.0810	
				357	0.1280	
				358	0.1580	
				359	0.1280	
				123	0.1240	
				131	0.0520	
				124	0.0200	
				129	0.1920	
				125	0.2050	
				128	0.0240	
				126	0.0216	
				127	0.1544	
				83	0.0360	
				93	0.1300	
			कुल योग	47	3.9566	हेक्टेयर
				या	9.773	एकड़
				या	15-12-14	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

प्रधेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 632.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1275 dated 18-5-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

### CASE SCHEDULE H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Buland Shaher	Sikandrabad	Dankaur	Ladpura	604	0.0560	
				546	0.0680	
				550	0.0880	
				549	0.0496	
				548	0.0904	
				543	0.1000	
				527	0.1460	
				528	0.1800	
				531	0.0640	
				530	0.0080	
				529	0.1630	
				525	0.0080	
				524	0.0880	
				523	0.0060	
				520	0.2360	
				519	0.0260	
				518	0.0192	
				488	0.0060	
				419	0.0760	
				435	0.0580	
				420	0.1980	
				421	0.1190	
				427	0.1610	
				429	0.0198	
				430	0.0030	
				428	0.0420	
				410	0.0590	
				409	0.0680	
				408	0.0210	
				407	0.0340	
				348	0.1280	
				349	0.0616	
				134	0.0520	

1	2	3	4	5	6	7
				352	0.0810	
				357	0.1280	
				358	0.1580	
				359	0.1280	
				123	0.1240	
				131	0.0520	
				124	0.0200	
				129	0.1920	
				125	0.2050	
				128	0.0240	
				126	0.0216	
				127	0.1544	
				83	0.0360	
				93	0.1300	
G. TOTAL				47	3.9566 Hectares	
				OR	9.773 Acres	
				OR	15-12-14 Bigha	

[No. L-14016/3/94—G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 633.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ. सं. 1279 तारीख 18-5-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रयॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

बाद-अनुसूची

एच.बी.जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हेक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	दनकोर	मुस्तकाबाद	19	0.1980	
योग				1	0.1980	
				या	0.488	हेक्टर
				या	00-15-12	एकड़ बीघा

[सं. एल-14016/3/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 633.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1279 dated 18-5-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline :

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

### CASE SCHEDULE

#### H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Bulandshahr	Sikrandrabad	Dankaur	Mustaqabad	19	0.1980	
TOTAL				1	0.1980 Hectares	
				OR	0.488 Acres	
				OR	00-15-12 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 634.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को अधिसूचना का.आ. सं. 1635 तारीख 25-6-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः केन्द्रीय प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।



## वाद-अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मीजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र, बीघा/एकड़/हेक्टे.	अन्य विवरण
बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	दन्कोर	घंघोला	66	0.1660	
				16	0.0336	
				65	0.1800	
				64	0.0310	
				23	0.0390	
				17	0.4340	
योग				6	0.8836	हेक्टेयर
				या	2.182	एकड़
				या	03-09-16	बीघा

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 634.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1635 dated 25-6-1994 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADE PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Bulandshaher	Sikandrabad	Dankaur	Ghanghola	66	0.1660	
				16	0.0336	
				65	0.1800	
				64	0.0310	
				23	0.0390	
				17	0.4340	
TOTAL				6	0.8836 Hectares	
				OR	2.182 Acres	
				OR	03-09-16 Bigha	

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 635.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ. सं. 1268, तारीख 18-5-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## बाद-अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र बीघा/एकड़/हेक्टर.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	दनकौर	सिरसा	451	0.0960	
				452	0.0180	
				453	0.0720	
				454	0.0030	
				455	0.0060	
				456	0.0160	
				444	0.1580	
				443	0.0030	
				442	0.0060	
				440	0.2220	
				445	0.1740	
				योग 11	0.7740	हेक्टेअर
				या	1.912	एकड़
					या 03-01-03 बीघा	

[सं. एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 635.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1268 dated 18-5-1994 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## CASE SCHEDULE

## H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Bulandshaher	Sikrandrabad	Dankaur	Sirsa	451	0.0960	
				452	0.0180	
				453	0.0720	
				454	0.0030	
				455	0.0060	
				456	0.0160	
				445	0.1740	
				444	0.1580	
				443	0.0030	
				442	0.0060	
				440	0.2220	
				TOTAL	11	0.7740 Hectares
				OR	1.912 Acres	
				OR	03-01-03 Bigha	

[No. L-14016/3/94—G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

का.आ. 636— भारत का राजपत्र दिनांक 16-7-94 के पृष्ठ संख्या 2466 व 2467 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा

(1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का.आ. 1623 दिनांक 25-6-94 के जनपद मथुरा की तहसील व परगना छाता के ग्राम-ऐंच की प्रकाशित हिन्दी सूची के स्तम्भ 5 व 6 में गाटा संख्या 197 के स्थान पर 187, 494 के स्थान पर 399 तथा गाटा संख्या 99 क्षेत्रफल 0.3030 के स्थान पर गाटा संख्या 99 क्षेत्रफल 0.3020 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 1995

S.O. 636.—In the gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S.O. 1623 dated 25-6-94 published on 16-7-94 at page No. 2467 to 2469 sub-section (1) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipeline (Acquisition of right of users in land) Act-1962 (50 of 1962) of Village-AINCH, Tehsil & Pargana—Chhata, Distt.-MATHURA in column 5, 6 & 7 be read plot No. 187, 399 instead of plot No. 197, 494 and plot No. 99 area 0.3020 instead of plot No. 99 area 0.3030, in Hindi version.

[No. L-14016/3/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

का.आ. 637 :- भारत का राजपत्र दिनांक 1-10-94 के पृष्ठ संख्या 3827 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का.आ. 2265 दिनांक 13-9-94 जनपद-मथुरा के ग्राम-गजू के स्थान पर नगला गजू पढ़ा जाय ।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 1995

S.O. 637.—In the gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S.O. 2265 dated 13-9-94 published on 1-10-94 at page No. 3841 sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right of

users in land) Act 1962 (50 of 1962) of Distt. Mathura, Tehsil & Pargana Mathura, Village Nagla Gaju to be read instead of Village Gaju.

[No. L-14016/3/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

का.आ. 638.—भारत का राजपत्र दिनांक 4-6-94 के पृष्ठ संख्या 1714 और 1715 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 1270 दिनांक 18-5-94 ग्राम-बिसायच, परगना-दनकौर, तहसील-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में ग्राटा संख्या 194 के स्थान पर 196 पढ़ा जाय ।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 1995

S.O. 638.—In the gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S.O. 1270 dated 18-5-94 published on 4-6-94 at page No. 1715 to 1716 sub-section (1) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of right of users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village-Bisaich, PARGANA—DANKAUR, TEHSIL—SIKANDRABAD, DISTRICT—BULANDSHAHER in column 5 be read plot No. 196 instead of plot No. 194.

[No. L-14016/3/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

का.आ. 639.—भारत का राजपत्र दिनांक 16-7-94 के पृष्ठ संख्या 2480 व 2481 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का.आ. 1628 दिनांक 25-6-94 ग्राम-लुहारली, परगना व तहसील-दादरी जनपद—गाजियाबाद को प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5, 6 व 7 में निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

प्रकाशित किया गया			शुद्ध पढ़ा जाये		
325	1549	0.2450	223	1549	0.1120
	1550		325	1550	0.1300
93	1342		93	1342	0.1150
	1345	0.1560	पोखर	1345	0.0410
380	1348		388	1348	0.0030
	1345	0.0240	पोखर	1345	0.0210
115	1356		115	1356	
	1381	0.2840		1381	0.2840
	1391			1361	
341	1525		341	1524	0.1840
	1526			1525	

1	2	3	4	5	6
	1527	0.0840			
	1523				
227	1527		1227	1526	
	1528			1527	
	1526	0.3427		1523	0.2420
133	1499		133	1499	
	1500			1500	
	1501	0.2820		1501	0.3710
	1502			1502	
	1503		569	1503	0.0070
404	1494			1494	
	1503	0.0960		1503	

[संख्या एल-14016/3/94/जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 1995

S.O. 639.—In the gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S.O. 1628 dated 25-6-94 published on

16-7-94 at page No. 2481 to 2483 sub-section (1) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village Luharli Pargana-Dadri, Tehsil-Dadri, Distt. Ghaziabad in column 5, 6 & 7 be read as follows.

PUBLISHED			TO BE READ		
325	1549	0.2450	223	1549	0.1120
	1550		325	1550	0.1300
93	1342		93	1342	0.1150
	1345	0.1560	Pond	1345	0.0410
380	1348		388	1348	0.0030
	1345	0.0240	Pond	1345	0.0210
115	1356		115	1356	
	1381	0.2840		1381	0.2840
	1391			1361	
341	1525		341	1524	0.1840
	1526			1525	
	1527	0.0840			
	1523				
227	1527		1227	1526	
	1528			1527	
	1526	0.3427		1523	0.2420
133	1499		133	1499	
	1500			1500	
	1501	0.2820		1501	0.3710
	1502			1502	
	1503		569	1503	0.0070
404	1494			1494	
	1503	0.0960		1503	

[No. L-14016/3/94 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 640 :—भारत के राजपत्र दिनांक 4-6-94 के पृष्ठ संख्या 1714 और 1715 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की

उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 1270 दिनांक 18-5-94 ग्राम-बिसायच, परगना-बनकौर, तहसील-सिकन्दराबाद उपपट्टा-बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में ग्राटा संख्या 199 के स्थान पर ग्राटा संख्या 198 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 640.—In the gazette of India Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S.O. 1270 dated 18-5-94 published on 4-6-94 at page No. 1715 to 1716 sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village-Bisaich, Pargana-Dankaur, Tehsil-Sikandarabad, Distt.-Bulandshahar in column 5 be read plot No. 198 instead of plot No. 199.

[No. L-14016/3/94 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 641:— भारत का राजपत्र दिनांक 4-6-94 के पृष्ठ संख्या 1738 से 1740 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 1281 दिनांक 18-5-94 ग्राम-दादपुर, दनकौर, परगना-दनकौर, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 181 क्षेत्रफल 0.0060 के स्थान पर गाटा संख्या 191 क्षेत्रफल 0.0060 तथा गाटा संख्या 267, 265, 263, 261, 260, 251, 29 और 99 के स्थान पर क्रमशः 367, 365, 363, 361, 360, 252, 39 और 79 पढ़ा जाय।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 641.—In the gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1281 dated 18-5-94 published on 4-6-94 at page No. 1740 to 1742 sub-section (1) of section-3 of the Petroleum & Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village-Dadpur Dankaur Pargana-Dankaur, Tehsil-Sikandarabad, Distt.-Bulandshahar in column 5 be read plot No. 191 area 0.0060 instead of plot No. 181 area 0.0060 and 367, 365, 363, 361, 360, 252, 39 & 79 instead of plot No. 267, 265, 263, 261, 260, 251, 29 & 99 consequently.

[No. L-14016/3/94 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 642:— भारत का राजपत्र दिनांक 16-7-94 के पृष्ठ सं. 2506 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 1639 दिनांक 25-6-94 ग्राम-बेला कला, परगना-दनकौर, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 74/8 के स्थान पर 75/8 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 642.—In the Gazette of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1639 dated 25-6-94 published on 16-7-94 at page No. 2507 sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962) of village Bela Kalan, Pargana Danaur, Tehsil Sikandarabad, Distt. Bulandshahar in column 5 be read plot No. 75/8 instead of plot No. 74/8.

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 643:— भारत का राजपत्र दिनांक 16-7-94 के पृष्ठ संख्या 2464 व 2465 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 1622 दिनांक 25-6-94 ग्राम-बरचावली, परगना व तहसील छाता, जनपद मथुरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 578/992 के स्थान पर 578/692 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 643.—In the Gazette of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1622 dated 25-6-94 published on 16-07-94 at page No. 2465 sub-section (1) of section 3 of Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of village Barcahwli, Pargana and Tehsil Chhata, Distt. Mathura in column 5 be read plot No. 578/692 instead of plot No. 578/992.

[No. L-14016/3/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995

का.आ. 644:— भारत का राजपत्र दिनांक 1-10-94 के पृष्ठ सं. 3824 व 3830 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 2265 दिनांक 13-9-94 ग्राम-रसूलपुर, परगना व तहसील मथुरा, जनपद-मथुरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा सं. 537 व 537 व के स्थान पर 541 व 541 व सही पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/3/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 1995

S.O. 644.—In the Gazette of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2265 dated 13-9-94 published on 01-10-94 at page No. 3838 and 3843 sub-section (1) of section 3 of Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right of users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of village Rasool Pur, Pargana and Tehsil Mathura, Distt. Mathura in column 5 be read plot No. 541 A and 541B instead of plot No. 537A and 537B.

[No. L-14016/3/94-G.P.]  
AREDHENDU SEN, Director

सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 645.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (मंच के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80% से अधिक कर्मचारी बन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. दूरदर्शन केन्द्र, रांची
2. दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर (म. प्र.)
3. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, जबलपुर
4. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, जोधपुर
5. दूरदर्शन केन्द्र (उच्च शक्ति प्रेषित), वाराणसी।

[संख्या ई-11011/1/93-हिन्दी]  
प्रेम कृष्ण गोरावारा, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 645.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices of the Ministry of Information and Broadcasting, the staff whereof more than 80 per cent have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. Doordarshan Centre, Ranchi.
2. Doordarshan Centre, Raipur (M.P.).
3. Doordarshan Maintenance Centre, Jodhpur.
4. Doordarshan Maintenance Centre, Jabalpur.
5. Doordarshan Centre (HPT), Varanasi.

[No. E-11011/1/93-Hindi]  
P. K. GORAWARA, Director (O.L.)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का.आ. 646:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के

पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/438/89 (डी 2 ए/आईआरबी-2)]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th February, 1995

S.O. 646.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95,

[No. L-12012/438/89-D.II-A/IR(B-II)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(46)/1990

## BETWEEN

Smt. Pushpa Lata Sahare, represented through the President, Bank Award Classes Bank Employees' Association (BCBEA) Nagpur (MS.)

## AND

The Zonal Manager, Bank of India, Kingswari, Nagpur (MS).

Presided in: By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES:

For Workman: Shri S. K. Patil.

For Management: Shri D. K. Biswal.

INDUSTRY: Banking.

DISTRICT: Nagpur (MS).

## AWARD

Dated, January 27, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/438/89-D-2-A dated 12th February, 1990, for adjudication of this following industrial dispute:—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of India, Nagpur in transferring Smt. Pushpa Lata Sahare from Nagpur to Katol is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Parties filed the joint application stating that no dispute between the parties exists because during the pendency of the dispute the workman has been transferred back to Nagpur and presently she is working in Nagpur main branch.

3. The reference is made for the justifiability of the transfer order of workman and in view of the aforesaid change in circumstances the reference has become infructuous.

4. The reference is declared infructuous and no dispute award is hereby passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

का.आ. 657.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ोदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के

पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल० 12012/394/92—आई. आर. बी.—2]  
बी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13rd February, 1995

S.O. 647.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-12012/394/92-IR(B-II)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(82)/1993

#### BETWEEN

The General Secretary, Bank of Baroda Employees Trade Union, Congress, Chouhan Niwas, Gondewada Road, Bodgaon, Nagpur-440013 (MS).

#### AND

The Regional Manager, Bank of Baroda, W.H.C. Road, Dharampeth, Nagpur-440010 (MS).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Union : None.

For Management : Shri R. P. Pathrava.

INDUSTRY : Banking. DISTRICT : Nagpur (MS).

#### AWARD

Dated, January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/394/92-IRBI dated 12-4-93 for adjudication of the following industrial dispute :—

#### SCHEDULE

"Whether the claim of Bank of Baroda Employees Trade Union Congress, Nagpur that Sri K. P. Gadre is entitled to get increment from 1989 even for his suspension period is justified in view of the clause 5 of the settlement dated 8-9-198 ? If not, to what relief is the workman entitled to?"

2. An application by the management was filed to the effect that the workman is dead and the case may be treated as infructuous. The notice was sent to the workman and none appeared for the workman/union. It appears that even the legal representatives of the workmen are not interested in the claim.

3. Consequently, due to the death of the workman the reference has become infructuous and it is answered accordingly.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.आ. 648.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. भारत कॉफ़िंग कोल लिमि. की पुत्तकी कोलियरी के प्रबन्धता के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—20012/225/92—आईआर (कोल—1)]  
ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 648.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. I) Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Putkee Colliery of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-2-1995.

[No. L-20012/225/92-IR(Coal-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)-(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 71 of 1993

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Putkee Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

#### AND

Their Workmen.

#### PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer

#### APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 31st January, 1995

#### AWARD

By Order No. L-20012/225/92-I.R. (Coal-I), dated 15-2-93 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Ramkanali Colliery in transferring S/Shri Rewa Mahato and Nageswar Sao in violation of 25.3 of certified Standing Orders which resulted in strike on 27-2-92, 29-2-92, 16-3-92, 17-3-92 and 18-3-92 is justified ? If not, whether the proposed deduction of eight days wages from the workers who were on strike on the aforesaid dates can be levelled ?"

2. The order of reference was received in this Tribunal on 10-3-93. Thereafter notice was issued to the sponsoring Union for filing written statement, but the same was returned back by the Postal Department with the endorsement that address was incomplete. Thereafter another notice was sent to the sponsoring Union which was also returned back.

3. On 21-10-94 Sri Ram Nath Singh, Secretary of United Coal Workers Union appeared. He submitted that he was in receipt of notice on which he had enquired into the matter and came to know that dispute was raised by the Colliery Kamgar Union. Sri S. K. Bakshi being its Secretary,



with address at Refugee Market, Temple Road, Dhanbad. He also informed that he was told that the aforesaid union already had settled the matter with the management.

4. Thereafter a fresh notice was issued to Sri S. K. Bakshi, Secretary of the Union at Refugee Market, Temple Road, Dhanbad, for filing written statement or informing the Tribunal about the settlement, by 15-12-94. Though the notice was duly received, no one appeared on 15-12-94. Thereafter a last chance was given to the sponsoring union to file written statement on 31-1-95, but none appeared on that date also.

5. It, therefore, appears that the sponsoring Union is not interested in pursuing the present industrial dispute.

6. Under the circumstances I render a 'no dispute' award in the present reference case.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.आ. 649.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अलप्पी के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल - 12012/340/92 - आई आर बी- 2]

वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 649.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Alleppey as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 14-2-95.

[No. L-12012/340/92-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ALLEPPEY

(Dated this the 20th day of January, 1995)

#### PRESENT:

Shri K. Kanakachandran, Industrial Tribunal  
I. D. No. 11/93

#### BETWEEN

The General Manager, UCO Bank (Head Office), 10-Bip-lahi Trailokya Maharaj Sarani (Brabourne Road), Calcutta-1.

#### AND

The General Secretary, Kerala Pradesh Bank Workers' Organisation (NOBW & BMS) Central Office, T. D. Road, Ernakulam-682 035 (Kerala).

#### REPRESENTATION:

Sri M Ramachandran, Advocate, Cochin-17.—For Management.

Party in person.—For Union.

#### AWARD

1. This industrial dispute between the management of UCO Bank and the General Secretary of Kerala Pradesh Bank Workers' Organisation (NOBW & BMS) was referred for adjudication to this Tribunal by the Government of India 453 GI/95—6

through an order No. L-12012/340/92/IR B-II dated 2-2-1993. The issue referred for adjudication reads as follows:—

"Whether the action of the management of UCO Bank in refusing to grant special leave to Sri. P. T. Rao, Zonal Secretary of the NOBW is justified? If not, to what relief the concerned office bearer of the union is entitled to?"

2. In the claim statement filed by the union it is stated that the workman concerned in this dispute is a Stenographer attached to Ernakulam Branch of management. He was elected as the Zonal Secretary of National Organization of Bank Workers (NOBW) on 8-2-1990. As a Zonal Office bearer of the union, he is entitled for 21 days of special leave for every calendar year and that is in accordance with para 13-39 of the First Bi-partite settlement between various Banks and Employees Organizations. Since the year 1970, special leave was being given in accordance with that settlement to the workman. By a letter dated 22-11-1991 the management Bank informed him that he was not entitled to special leave as per the bi-partite settlement. Various correspondences made later in that connection did not yield any result. The action of the management in denying special leave benefits to him is a breach of settlement of the year 1966. That is also an unfair labour practice enumerated in the Vth Schedule of the I. D. Act. On account of the action of the management, several days of special leave availed by him were converted as earned leave (privilege leave) and leave on loss of pay. Because of that, he has to suffer heavy monetary loss and also has to forego earned leave to his credit. Therefore the plea is to declare illegal the denial of special leave and to declare it is violative of Clause 13-39 of the First Bi-partite Settlement dated 19-10-1966. There is also the plea for directing the Management to compensate monetary loss suffered by the workmen and to restore fully the special leave illegally denied.

3. In the counter statement filed by the management, they had explained the position maintained by them so far. According to them, the union in this dispute is not a major representative of the Bank Workers and therefore its office bearers cannot insist for leave benefits as contemplated in the bi-partite settlement of the year 1966. The workman concerned had availed the special leave fully knowing that for the same he was not entitled. In the settlement signed on 12-10-1970 and 1-8-1979 the NOBW was a party, but they were not parties in 1983 settlement or in the settlement signed thereafter. The benefits contemplated in the various settlement were enjoyed by the members of NOBW for some period. On the expiry of 1966 settlement, all the unions including NOBW issued formal notice of termination in accordance with Sec. 19 of the I. D. Act. However in the industry wide settlement dated 29-6-1990 entered into later, a Clause was incorporated to the following effect:—

"It is clarified that the facility of special leave as provided for Clause 13.39 of the 1st Bipartite Settlement dated 19-10-1966 shall be available to the AIBEA, NCBE and INBEF."

4. Knowing well about this, the workman had been availing special leave with the claim that as a member of the NOBW, he is also entitled for special leave as in the case of office bearers of other unions who signed settlement with the respective managements.

5. It is unnecessary to go in detail of the controversial issue now raised for arriving at an independent decision by this Tribunal. The matter is fully covered by a decision of the Kerala High Court in Writ Appeal No. 1239 of 1992. In this connection it is relevant to quote a few portions from the judgment dated 23-9-1993 in the above Writ Appeal. Admittedly the union concerned in this dispute viz., NOBW was not a party to the bi-partite settlement dated 19-10-1966. Basing on that position, in para 8 and 9 of the judgment the High Court observed:

"8. It is revealed from paragraph 4 of the counter affidavit filed by the management-second respondent that Ext. P1 settlement expired on 31-12-1968 and, thereafter, the unions including NOBW gave notice of termination to the Indian Bank Association in terms of Section 19(2) of the Industrial Disputes Act, 1947. Therefore, NOBW and its affiliates, such as the appellant's associations, cease to be eligible for

clause 13.39. There was a second Bipartite settlement in 1972 to which NOBW was a party. Then there was a third bipartite settlement on 31-8-1979 to which NOBW was a party. Thereafter, there was a fourth Bipartite settlement on 8-9-1983 which was not signed by NOBW. Once again, there was a fifth Bipartite settlement on 10-4-1989 and this was also not signed by NOBW. There was then a supplementary agreement on 29-6-1990 which was also not signed by NOBW.

9. In other words, while Ext. P1 settlement stood terminated under Section 19(2) by notice issued by the associations including NOBW and clause 13.39 of the Principal Agreement dated 9-11-1966 stood inapplicable thereafter, NOBW signed only the second Bipartite agreement of 1972 and the third Bipartite agreement dated 31-8-1979. But it did not sign the subsequent Bipartite agreements dated 8-9-1983, 10-4-1989 or the supplementary agreement dated 29-6-1990. Alongwith the counter affidavit, the Bipartite settlement dated 10-4-1989 (Ext. R2) (a) and the supplementary settlement dated 29-6-1990 (Ext. R2)(b) have been produced. Ext. R2(b) dated 10-4-1989 mentions in Clause 3 as follows :

"The provisions of the said Awards, the First Bipartite Settlement dated 19th October 1966 and/or other subsequent Settlement(s) including the above mentioned separate settlement hereinafter collectively referred to as said settlements shall stand amended, modified or superseded to the extent and in the manner detailed hereinunder."

The provisions which are not amended shall, however continue. Ext. R2(b), the supplementary settlement dated 29-6-1990 contains clause 11 relating to 'Special leave' as follows :

"It is clarified that the facility of Special Leave as provided for in Clause 13.39 of the First Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 shall be available to the AIBE, NCBE and INBE."

6. From the above portion extracted, now it is clear that for enjoying the benefits contemplated in Clause 13.39 of bipartite settlement dated 9-11-1966, the union in this dispute is not entitled. In para 11 of the judgment it was further observed as follows :—

"11. For the aforesaid reasons, we hold that the appellants cannot rely on clause 13.39 of the settlement dated 19-10-1966 adopted in the Bipartite settlement. Ext. P1 dated 9-11-1966 in as much as the same stood terminated validly by a notice issued under Sec. 19(2) of the Industrial Disputes Act by the Employees' association including NOBW. Though NOBW was a party to the second Bipartite settlement of 1972 and the Third Bipartite settlement dated 31-8-1979. It is not contended before us for the appellants that those two settlements contained any clause similar to Clause 13.39. Learned counsel for the Bank mentioned before us that those two agreements did not contain any such clause. The union to which appellants are affiliated, namely, NOBW not being a party to the subsequent settlements namely, the Fourth Bipartite settlement dated 8-9-1983, Fifth Bipartite settlement dated 10-4-1989 and the supplementary agreement dated 29-6-1990, the appellants cannot claim the benefits which the other unions have claimed. We, therefore, hold that the appellants cannot rely upon clause 13.39 of the Original Settlement dated 19-10-1966 and claim the 'special leave facility' unconditionally."

7. In view of the clear pronouncement of the High Court, no doubt, for the special leave benefits contemplated in the settlement of the year 1966, none of the office bearers of NOBW are entitled.

8. The next question is whether the denial of special leave is in violation of Sec. 9(A) of the I. D. Act. Regarding that also, the High Court observed as follows in Paragraph 13:

"13. We are of the view that the 'special leave' facility in clause 13.39 of the 1966 settlement, even if it is

to be alternatively assumed not to have been terminated under Sec. 19(2) contrary to paragraph 4 of the counter affidavit of the second respondent. It was only a concession of privilege and not a 'condition of service'. Firstly, it cannot be compared with a general condition of service applicable to all employees. It is restricted to the office bearers and further, it is not in any way connected with attending meetings connected with Banking employees. Clause 13.39 is a facility applicable even when the office bearers are attending ordinary trade union meetings. It is attached to these employees only so far as they continue as office bearers. Such a special leave facility is, in our opinion, a mere concession. We do not think that it comes under 'customary' concession or privilege. In this connection, learned counsel for the respondent has relied upon the decision in *Workmen of Indian Bank v. MGMT of Indian Bank* (1985 1 LLJ 6). That case related to a duty relief given to office bearers of a trade union and it was held to be a mere concession and not a 'condition of service'. The said judgment was affirmed in *WA 1045 of 1984 (Madras)* dated 26-10-1984. We are in agreement with this view".

9. In view of the clear pronouncement by the High Court on the issue raised by the union in their claim statement, this reference can only to be answered rejecting the claim of the Union.

Award is passed accordingly.

(Dated this the 20th day of January, 1995).

K. KANAKACHANDRAN, Industrial Tribunal

## APPENDIX

(I. D. No. 11/93)

Witness examined on the side of the Management :—

Nil

Witness examined on the side of the Union :—

Nil

Exhibits marked on the side of the Management :—

Nil

Exhibits marked on the side of the Union :—

W1 : Letter No. M/STF/925/91 dated 22-11-1991 from UCO Bank, Ernakulam Branch.

W2 : Letter dated 23-11-1991 of Sri P. T. Rao.

W3 : Letter No. M/STF/1026/92 from the UCO Bank, Ernakulam Branch.

W4 : Letter dated 15-1-1992 of Sri P. T. Rao.

W5 : Letter No. M/STF/1060/91-92 dated 18-1-1992 from UCO Bank, Ernakulam Branch.

W6 : Letter No. ALC/SPL/03/91-92 dated 15-1-1992 from Kerala Pradesh Bank Workers' Organization, Ernakulam.

W7 : Letter No. M/1132/91-92 dated 17-2-1992 from UCO Bank, Ernakulam Branch.

W8 : Letter No. ALC/SPI /2633/91-92 dated 18-8-1992 from Kerala Pradesh Bank Workers' Organization.

W9 : Minutes of Joint Discussions/Conciliation Proceedings dated 18-8-1992.

W10 : Failure of Conciliation Report dated 25-8-1992.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.भा. 650.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम. पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल - 29011/5/91 - आईआर (एमआईएससी)]

बि. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 650.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/5/91-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(188)/1991

BETWEEN

S/Shri Y. M. Nirwan, Driver and R. B. Sirdar, Driver-cum-Conductor, represented through the General Secretary, Maharashtra State Mining Corporation Employees Union, C/o Sri M. N. Kishasagar, Plot No. 139, Abhyankar Nagar, Nagpur-10 (MS).

AND

The Chairman-cum-Managing Director, Maharashtra State Mining Corporation Ltd., 5, Abhyankar Nagar, Nagpur-10 (MS).

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Workmen : None.

For Management : Shri V. S. Varma.

INDUSTRY : Mining DISTRICT : Nagpur (MS)

## AWARD

Dated : January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/5/91-IR(Misc) Dated 14-10-1991, for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

- I. "Whether the management of MSMC is justified in not regularising S/Sh. Y. M. Nirwan, Driver and Shri R. B. Sirdar, Driver-cum-Conductor in the instant dispute and if not to what relief the workmen are entitled to?"
- II. "Whether the management is justified in not paying equal wage to the workmen in the instant dispute on par with that of the regular workman and if not to what relief the workmen are entitled to?"

2. Parties have not filed the statement of claim inspite of repeated notice sent to them, the Notice was sent to the workmen on 25-10-91, 10-12-91, 20-1-92, 2-4-92 and 16-8-94, but the workmen have not appeared. Management appeared on many dates. Ultimately the management prayed to close

the case on the ground that the workmen are not interested in the case and their claim prayed under the reference. As the workmen have not appeared nor filed the statement of claim, the prayer of the management to close the case is just and proper.

3. Consequently, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.भा. 651.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर (एम. पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल - 29011/10/91 - आईआर (एमआईएससी)]

बि. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 651.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/10/91-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(193)/1991

BETWEEN

Shri Ramesh Bhimrao Ingole represented through the Secretary, Maharashtra State Mining Corporation Employees Union C/o Shri M. N. Kishasagar, Plot No. 139, Abhyankar Nagar, Nagpur-10.

AND

The Chairman-cum-Managing Director, Maharashtra State Mining Corporation Ltd., 5, Abhyankar Nagar, Nagpur-10.

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Workman : None.

For Management : Shri V. S. Varma.

INDUSTRY : Mining DISTRICT : Nagpur (MS)

## AWARD

Dated : January, 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/10/91-IR (Misc.) Dated 22-10-1991 for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd., Nagpur for not regularising the services of Shri Ramesh Bhimrao Ingole, helper in the regular cadre of the Corporation w.e.f. 1-7-1988 is justified? If not, so then what relief the workman concerned is entitled to?"

2. Workman or the management has not filed the statement of claim and the written statement. The notice to the workman was issued on 31-10-91, 13-12-91, 8-1-92, 2-4-92, 12-8-92 and 16-8-94 for filing the statement of claim. The workman never appeared or he has filed the statement of claim inspite of repeated notices in the last three years.

3. Consequently, it is clear that the workman is not in interest pursuing the claim. No dispute award is therefore passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.प्र. 652.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध-तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम. बि.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल - 29011/37/90 - आई प्रार (विविध)]

वि. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 652.—In pursuance of Section 1 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/37/90-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(50)/1992

BETWEEN

The Secretary, Maharashtra State Mining Corpn. Employees Union C/o Shri N. N. Kshirsagar, Plot No. 139, Abhyankar Nagar, Nagpur (MS)-44010.

AND

The Chairman-cum-Managing Director, Maharashtra State Mining Corpn. Ltd., 5, Abhyankar Nagar, Nagpur (MS)-440 010.

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Union : None.

For Management : Shri V. S. Varma.

INDUSTRY : Mining

DISTRICT : Nagpur (MS)

AWARD

Dated : January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification no. L-29011/37/90-IR (Misc.) Dated 9-3-92 for adjudication of the following industrial dispute :—

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Maharashtra State Mining Corp. Ltd. Nagpur by rejecting the

claim for payment of Project Allowance at the rate of 20 per cent on the revised pay scale of the employees is justified, if not so, what relief the workmen are entitled to ?"

2. Parties failed to appear on 27-5-92 even after the service of the registered notice on 30-3-92 and the workman has not filed the statement of claim although notice was sent to the union on 12-8-92 and 10-8-94. Management also informed the Union to file the statement of claim. In spite of the repeated notices to the Union to file the statement of claim neither the workmen or the Union appeared nor filed statement of claim. The prayer of the management to close the case, as the workmen are not interested in the case, is just and proper. The minor dispute of 20 per cent Project Allowance on the revised scale was demanded by the employees and it is clear that the Union is not interested in pursuing the dispute.

3. Consequently in the aforesaid circumstances, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.प्र. 653.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम.पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/46/88-डी-3-बी]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 653.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mineral Exploration Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29012/46/88-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(83)/1990

BETWEEN :

Shri S. K. Jain, represented through the General Secretary, Indian National Mineral Exploration Corporation Employees Union, Bansal Villa, Ka'ol Road, Nagpur (MS).

AND

The Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd, Seminary Hills, Nagpur-440 006 (MS).

Presided in.—By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES :

For Workman.—Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management.—Shri Govind Mishra, Advocate.

INDUSTRY : MECL

DISTRICT : Nagpur (MS).

## AWARD

Dated, the 30th January, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L 29012/46/88-D.III(B) dated 15-3-1990 for adjudication of the following industrial dispute :—

## THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur in imposing the punishment on Shri S. K. Jain, Asstt. (Personnel) of withholding his two increments in addition to charging penal interest is justified. If not, what relief is the employee concerned entitled to?"

2. Parties have filed the statement of claim and written statement and issues were framed and the case was posted for evidence. On 15-9-92 the management filed an application along with the Memorandum of Settlement. Notice was issued to the workman for verification of the Settlement. The workman did not appear for verification of the Settlement. Management filed a receipt of payment of Rs. 4,500 towards the full and final settlement of the claim under reference. The reference was regarding non-payment of increments and interest. From the perusal of the settlement and the receipt of Rs. 4,500 it is clear that the workman has settled the claim out of Court. Consequently, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.भा. 654.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम.पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 फरवरी, 1995 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/38/92-माई आर]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 654.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M.P. State Mining Corporation, Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/38/92-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(253)/1993

## BETWEEN :

The General Secretary, M. P. Khadan Swatantra Mazdoor Sangh, Baradwar, District Bilaspur (MP).

## AND

The Managing Director, M. P. State Mining Corporation Ltd., Suryay Complex, Opposite Habibganj Police State, Area Colony, Phopal (MP).

Presided in.—By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES :

For Union.—Shri T. Kashinath,

For Management.—Shri B. S. Bisen, Advocate.

INDUSTRY : Mining

DISTRICT : Bilaspur (MP).

## AWARD

Dated, 23rd January, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/38/92-IR(Misc.) dated 22-12-93 for adjudication of the following industrial dispute :—

## THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of M.P. State Mining Corporation Ltd. Bhopal is justified in paying incentive amount as reward only to the employees of M. P. State Mining Corporation Ltd. vide their letter dated 28-6-1991 excluding miners working in the mine on piece rate system? If not, what relief the workmen working in mine on piece rate entitled to?"

2. Parties have not filed the statement of claim. Shri K. C. Bajpai, Secretary-cum-General Manager, M. P. State Mining Corporation filed the Tripartite Settlement arrived at between the parties on 15-6-93. The Union has verified the Settlement and pray to pass a no dispute award. According to the Tripartite Settlement arrived on 15-6-93 between the management and the Union an incentive of Rs. 100 per piece rate labour has been given and the copy of the Agreement is filed along with the Settlement. Settlement is just and accepted.

3. Consequently, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.भा. 655.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मोदी सिमेंट लिमिटेड के प्रबन्ध तन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 फरवरी, 1995 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-29011/28/92-माईआर (मिसिलेनी.)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 655—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of MODI Cement Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/28/92-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer  
ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(132)/1993

BETWEEN :

Shri Ishwar Chand Verma S/o, Pradmun Singh, Modigram (Wawan) Tahsil Baloda Bazar, District Raipur (M.P.)

AND

The Director, Modi Cement Ltd., Modigram (Wawan),  
P.O. Baloda Bazar, District Raipur (M.P.).

Presided in.—By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman.—Himself.

For Management.—Shri S. K. Bhaduri, Advocate.

INDUSTRY : Cement. DISTRICT : Raipur (M.P.)

AWARD

Dated, 25th January, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/28/92-IR (Misc.) dated 22-6-1993 for adjudication of the following industrial dispute :—

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Modi Cement Ltd. Biloda bazar, Distt. Raipur (MP) in dismissing the services of Shri Ishwar Chand Verma, Crusher/Stacker Operator w.e.f. 21-8-1991 is justified and proportionate for the misconduct alleged to have committed? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. The workman filed the statement of claim. Management has not filed the statement of claim or the written statement.

3. The workman has filed an application before the Court for the withdrawal of the reference and it is alleged that the management has taken decision to reinstate him.

4. As the workman has not pressed the reference no dispute award is hereby passed. Parties to bear their own costs

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

का.घा. 656.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र स्टेटमाइन कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, प्रबन्ध में निर्विष्ट

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम.पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-29011/50/91-माईनार (विवाद)]

बी.एम.डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th February, 1995

S.O. 656.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maharashtra State Mining Corporation and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-29011/50/91-IR (Miso.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(143)/1992

BETWEEN :

The Secretary, Maharashtra State Mining Corporation Employees Union C/o. Shri M. N. Kshirsagar, Plot No. 139, Abhyankar Nagar Nagpur. (MS)-440001.

AND

The Chairman-cum-Managing Director, Maharashtra State Mining Corp. Ltd., 5, Abhyankar Nagar, Nagpur (MS)-440001.

Presided in.—By Shri Arvind Kumar Awasthy

APPEARANCES :

For Workman.—None.

For Management.—Shri V. S. Varma.

INDUSTRY : Mining DISTRICT : Nagpur (MS).

AWARD

Dated, the 30th January, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/50/91-IR (Misc.) dated 4-6-1992 for adjudication of the following industrial dispute :—

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Maharashtra State Mining Corporation Limited, Nagpur in not measuring the Ore produced by the workmen of Patgowari Dolomite Mine through Weighbridge is justified? If not so, then what relief the workmen are entitled to?"

2. Notice to the parties to file the statement of claim and written statement has issued on 6-7-92 and the case was posted on 25-8-92, but neither the parties appeared nor the statement of claim filed by the parties. Again on 16-8-94 the parties were directed to file the statement of claim on to file the statement of claim, but the workman neither 5-10-94 and the management also informed the workman

appeared nor file the statement of claim. The minor dispute between the management and the workman was raised regarding the measurement of Ore produced by the workmen. It is clear that the workmen are not interested in pursuing the dispute.

3. Consequently, the prayer of the management to close the case is just and proper and no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.अ. 657.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धनतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या: एल-12012/414/92-आई भार(वी-2)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 657.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 15-2-1995.

[No. L-12012/414/92-IR (B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD  
PRESENT :

Shri D. K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947  
Reference No. 27 of 1993

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of UCO Bank, Patna and their workmen.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri B. Prasad, State Secretary, UCO Bank Employees Association.

On behalf of the employers—Shri Sarkar, Law Officer.

STATE : Bihar INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 7th February, 1995

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to

this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/414/92-IR (B-II), dated, the 26th March, 1993.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of UCO Bank in dismissing Shri A. P. Gupta from the services of the Bank justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

2. In the instant reference the action of the management of UCO Bank, Patna dismissing Shri A. P. Gupta from his services of the said Bank has been challenged by the concerned workman commencing the order of dismissal on and from 7-5-1992 after performing the domestic enquiry by the management.

3. The said A. P. Gupta (hereinafter referred to as workman) filed a W.S. stating several facts challenging the legality and validity of the enquiry and order of dismissal upon the following ground which are stated in a nutshell.

4. The concerned workman has stated in his W.S. filed on 6-9-93 to the effect that he joined in service in the said Bank (UCO Bank) on 8-9-69 in the cadre of clerks and since his joining he is discharging his duties faithfully and diligently to the satisfaction of the Bank management and thereafter he was transferred to Joghani while a new branch was opened there on and from 13-10-1969. He is working there with good reputation diligence and for his brilliant service career he was appreciated by the highest management in writing vide Bank's letter dated 8-8-1973.

5. The concerned workman admitted the commission of some irregularities in between 27-7-85 and 15-7-86 and it is admitted that for such acts the management straightway issued letter in the form of chargesheet on 30-7-1988 mentioning therein seven head charges asking the concerned workman to accept or deny the said charges within 15 days from the date of the receipt of the said letter though no explanation was called for earlier nor any copy of statement leading to hold domestic enquiry was supplied prior to it. It is further stated in the W.S. that one months time was prayed for and gave reply to the charges allegedly levelled against him by letter dated 8-9-88 explaining his position. But being not satisfied the management started domestic enquiry for the charges levelled against him as per order of Asstt. General Manager who is the disciplinary authority and appointed Enquiry Officer as well as Presenting Officer. The said appointment and starting of proceeding were communicated to the concerned workman and he raised objection to it for the reasons stated therein as he apprehended to be victimised for rivalry over the union matter with the Enquiry Officer as well as Presenting Officer. It was turned down without paying and need.

6. On enquiry which was started on 7-3-89 and ended on 5-10-89 this workman was found guilty of the charge levelled against him though no document nor any satisfactory evidence by examining any competent witness was produced. Even the management failed to establish any loss or damage suffered by the management for the alleged activity of the concerned workman and without holding the enquiry in proper and legal manner a cryptic report was submitted and the disciplinary authority proposed punishment of dismissal to the workman by issuing show cause notice to the workman vide letter No. Misc./Vig./90/26 dated Nil fixing personal hearing on 26-4-90. On receipt of such show cause notice a prayer was made with a request to supply the copy of the enquiry report and fixing date on 26-4-90 for filing reply to show cause. But the disciplinary authority failed to supply the copies sought for and in the meantime the disciplinary authority was transferred to other post. Thereafter Zonal Manager who was the disciplinary authority issued notice on 30-12-91 to this workman for his personal hearing on 13-1-92. The workman prayed for his defence which was turned down by the Zonal Manager and hereby he was compelled to submit his reply to show cause and the said Zonal Manager conducting the personal hearing on 13-1-92 passed order of dismissal on 7-5-92 while he was under order of transfer. That order could not be served upon the workman as he

proceeded on leave from 11-5-92 and while he came to join on 21-5-92 with a medical certificate he was not allowed to join for and in the meantime the matter was referred to the ALC (C) Patna for the order of proposed dismissal vide letter No. 13-5-92 raising a dispute inviting attention of the management to Section 33 of the I. D. Act. Accordingly on and from 21-5-92 the management stopped the work of the concerned workman though he received the order of dismissal on 30-5-92. Finally the proceeding before the ALC (C) Patna ended having no result due to adamant attitude of the management.

7. According to the workmen the said order of dismissal is illegal and the order which was passed on 21-5-92 is in a way of retrenchment under Section 2(oo) of I. D. Act, 1947 and the management failed to follow the procedures laid down for such retrenchment. It is alleged further that the domestic enquiry was conducted by the management without observing the formalities in this regard and the enquiry report was biased and without foundation and the action taken by the Zonal Manager was illegal as he was not the disciplinary authority nor he was competent to do so and there has been miscarriage of justice and the failure of conciliation report was sent to the Government of India resulting reference to this Tribunal for the relief of his reinstatement with full back wages with 20% interest holding the order of dismissal to be illegal and unjustified and for other adequate relief.

8. From the side of the management W.S.-cum-rejoinder was filed on 16-3-94 stating inter alia that the workman under award was an employee of the management and no doubt he was appreciated for his past work which has no relevancy for the dispute to be adjudicated by this Hon'ble Tribunal.

9. It is stated further that the concerned workman Shri Gupta had committed certain illegalities of routine nature during the year 1985-86 in Joghani branch resulting and indulging in grave financial irregularities and causing serious loss to the Bank and for the same an investigation was taken place in which those irregularities were detected and for the same a chargesheet dated 30-7-88 was issued to him. The concerned workman was given opportunity for inspection of documents upon which the management relied to establish the charges though the copies of the said documents were not supplied with and thereby they had caused no prejudice to the concerned workman. Further statement of the management is that the concerned workman Shri Gupta in his reply to the chargesheet admitted almost all the charges levelled against him with certain explanations which are practically nothing but lame excuse. The disciplinary authority in an enquiry proceeding being appointed by the competent authority hold an enquiry after hearing the management through the Presenting Officer and the concerned workman Shri Gupta and considered the relevant documents, facts and circumstances and the Enquiry Officer came to the conclusion that most of the charges levelled against him were well founded as mostly were admitted by the concerned workman Shri Gupta and were supported by the documents, registers maintained in the Bank. It is stated further that though some persons were examined by Shri Gupta to establish that the management did not suffer any loss in any manner can have got no relevancy as because irregularities remained irregularities inspite of the statement of some persons if those are establishment from the documents itself. It is strictly denied that the enquiry was not performed after observing the legal formalities nor it has accepted that the result of the enquiry is an outcome of any influence or rivalry between two unions. Thereby the order of dismissal by the appropriate authority with reference to the finding of the Enquiry Officer was with foundation and were supported by the materials but not biased as alleged by the concerned workman. The said workman preferred an appeal against the said order of dismissal pursuant to the report of the Enquiry Officer but that was also found baseless and the recommendation of order of dismissal was sustained and thereby the concerned workman was dismissed from the service legally and validly.

10. It is denied that it is a case of retrenchment but it is a case of dismissal so there is no scope of following the procedure of retrenchment as complained of and the order of dismissal was passed by the competent person and the procedures adopted in the enquiry were legal and proper one and the concerned workman challenged this order of dismissal passed against him on 7-5-93 in the three forums by one taking up with the ALC (V) Patna, (2) filing appeal before the Appellate authority at Calcutta and (3) Writ petition before the High Court, Calcutta. Lastly it is submitted that here is no merit in the Written Statement filed by the workmen and the order of dismissal to be sustained holding the same to be legal and valid one.

11. On 18-3-94 the concerned workman through State Secretary Employees Association filed a rejoinder to the W.S. of the management stating that he got appreciation from higher authorities and he did not commit any financial irregularities causing any damage to the Bank and he charges were not proved by the management properly. But again he has admitted that he definitely committed certain mistakes which often happen during the course of working. According to him factum of both the Enquiry Officer and the Presenting Officer belonging to another union having rivalry with him had influenced the result of enquiry. It is denied any loss to the extent of Rs. 89,912 alleged to be caused to the management as no account holder has come forward to support such allegation of the management and the order of dismissal was passed by an official who had no such authority and there was miscarriage of justice for not adhering Section 33 of the I. D. Act and thus prayed for reinstatement as stated earlier.

12. From the trend of the W.S. of the concerned workman apparently it appears that he has challenged the procedures and the paraphernalias of the enquiry in which he was held liable for commission of the charges levelled against him.

13. At the very outset I am of the opinion that the order dated 25-4-94 passed by my predecessor-in-office will give reply to it. In the said order the learned Presiding Officer of this Tribunal had already referred that in course of argument the learned counsel for the workman has already admitted the fairness and propriety of the domestic enquiry. If that be so it is futile to re-agitate that point again that the enquiry was not held fairly and properly and thereby I close the said chapter for the purpose of adjudication of the points in issue involved before this Tribunal and I hold that the argument advanced from the side of the workman on this point has got no foundation and I proceed to deal with the matter holding that the domestic enquiry was proper and fair one.

14. The questions which invite my decisions are as follows :—

1. Whether the Enquiry Officer arrived to his decision on consideration of the materials submitted by the management to establish the charges levelled against the concerned workman with reference to the oral and documentary evidence.

2. If so, whether the punishment imposed upon the concerned workman is disproportionate and excessive in comparison with the alleged misconduct.

15. It is admitted position that already by order dated 25-4-94 passed by my predecessor-in-office it was conceded by both the parties that the enquiry was held in proper and fair manner. Be that as it may, it is mentioned that from the side of the management no oral evidence was adduced only for the reason that most of the charges levelled against the concerned workman were admitted subject to the explanation that all were done in good faith and those were regularised in due course of time and for the said acts amounting to irregularities no loss was suffered by the Bank in strict sense.

16. In this premises I am not forgetful of the Written Statement filed by the management whether at the relevant place the management also alleged the said



variations and departures to be irregularities not illegalities. We cannot ignore the facts that there is difference between irregularities and illegalities as because irregularities are curable but illegalities are not so.

17. Let me refer the report of the Enquiry Officer along with the chargesheet and the reply of the concerned workman marked Ext. M-1, M-2 and M-6.

18. In the chargesheet Ext. M-1 the following charges were levelled against the concerned workman :—

"Ext. M-1

Ref : Misc/Vig-88/273

Dated 30-7-88.

Sri A. P. Gupta,  
(PFM No. 10909)  
Special Assistant,  
UCO Bank,  
Jogbani Branch

Dear Sir,

You, while functioning as Special Assistant at Jogbani Branch (hereinafter referred as branch committed several commission and omissions, irregularities/misappropriation of fund which interim of the provision clause under 19.5 of the Bipartite Settlement constitutes gross misconduct on your part, particulars where of are given below.

1. You, wrongfully, knowingly allowed withdrawal in SB/account No. 2022 for Rs. 2600 in the name of Master Urtam Choudhury (Minor) on the diverse dates where withdrawal slip was signed by the minor above named and not by his natural guardian.
- (b) A withdrawal slip for Rs. 2000 dated 31-7-85 signed by Gvartri Devi in English version where as per AOF it would be in Hindi and thus without verifying the signature as per Specimen card and passed the withdrawal slip by your signature for payment.
- (c) Withdrawal slip for Rs. 1650 dated 3-9-85 signed by Shyam Sunder Choudhury you verified the signature and passed the W/S for payment, whereas the signature of Shyam Sunder Choudhury does not tally with the specimen signature card. Above all it was reported that Sri Shyam Sunder Choudhury died on 1-1-82 in Kathmandu Hospital.
- (d) Withdrawal slip for Rs. 1000 dated 25-2-86 signed by S. S. Choudhary signature on the W/S does not tally as per specimen signature card of the A/c but in spite of that you verified the signature and passed for payment.

Your above act is prejudicial to the interest of the Bank also involving serious financial loss ignoring the Bank's prescribed procedure and causing fraudulent withdrawals of the amount from the above referred SB A/c Nos. and thus confirming your mala fide intention which is gross misconduct in terms of the provision of the Bipartite Settlement under clause 19.5(d)(i).

You wrongfully, knowingly and ignoring the prescribed norms of the Bank allowed withdrawal in SB A/c 2023 of Miss Urmila Choudhary (Minor) the Guardian/Father of the said minor died on 1-1-82 and even thereafter on diverse dates as follows :—

1. W/S. for Rs. 1500 dated 14-9-85 signed by S. S. Choudhury.
2. W/S. for Rs. 1000 dated 25-9-85 signed by S. S. Choudhury.
3. W/S. for Rs. 500 dated 3/4-10-85 signed by S. S. Choudhury.
4. W/S for Rs. 500 dated 22-8-86 signed by S. S. Choudhury.

All referred withdrawals have passed for payment by you. A false credit entry of Rs. 5000 was made by you on 10-7-86 in SW A/c 3480 in the name of Sri Poonam Chan Sharma. On scrutiny it was

found that on 10-7-86 was a holiday and there is no such credit voucher on the day. Thereafter, the credit entry dated 10-7-86 was cut off and subsequently a debit entry without mentioning any date for Rs. 7000 through Cheque No. 911999 was passed by you in the said A/c on the strength of credit voucher dated 10-7-86. The false credit entry dated 10-7-86 by which increased the balance in the A/c was corrected on or after 26-9-86.

A credit voucher filled up by you for Rs. 5000 dated 2-8-86 was credited in the said a/c. bearing your signature that the SB A/c. 601/3 debited but the W/S for Rs. 7582 of SB A/c. 601/3 does not bear the genuine signature of the A/c. holder, which was passed by you and out of Rs. 7582 debited from SB A/c. 601/3 Rs. 5000 credited to SB 3480 and 2582 credited in SB a/c. 3943. The same amount of Rs. 7582 was credited on 30-9-85 in the account of 3480 by depositing cash. The account was introduced by you. The above act confirms your wilful attempt to cause damage to the property of the Bank and to involved the Bank in serious loss.

4. A false credit of Rs. 6200 was given on 14-3-85 by you in the SB A/c. No. 3784 stands in the name of Smt. Sharda Malla and Rajesh Malla thus increased the balance on date which signed by you. There is no such credit voucher dated 14-3-85 with the days voucher.

A withdrawal slip for Rs. 13,187 dated 15-7-86 which was filled up by you debited in the SB A/c. No. 3784 and the debited balance was initiated by you. The said voucher is well with the days voucher. But the debit entry was struck off by you in the ledger. The signature on the W/S does not tally with the signature as per specimen signature card of the A/c. holder. The withdrawal of Rs. 13,187 dated 15-7-86 was credited in SB A/c. No. 4522/26 in two separate credit vouchers which was signed by you in token of support that the SB A/c. No. 3784 is debited. Thus you played a mischievous game in both the A/c. once you debited SB A/c. 3784 and 4528/26 credit SB A/c. 4528/26 in the name of Sri Radha Mohan Prasad whose a/c was introduced by you. All vouchers are prepared and signed by you. In the same a/c. i.e. SB A/c. No. 3784 the following W/S debited ignoring the fact that the signature of A/c. holders completely posted in the ledger by you, passed for payment and signature verified by you with ulterior motive

(a) W/S for 8345 dated 14-8-86 cash paid.

(b) W/S for Rs. 5800 dated 14-8-86 Transfer debit entry and credited in to SB a/c. 3943 while the pay-in-slip was not signed by the depositor where as you have prepared with your own handwriting the pay-in-slip and credited with ulterior motive.

(c) W/S for Rs. 2,000 dated 18-8-86 cash payment.

5. You knowingly with the ulterior motive prepared a false credit of Rs. 7,100 on 11-3-85 in the SB A/c. No. 1198/5 stands in the name of Sandip Kr. Bhattacharya and Mrs. Shefale Bhattacharya, which was posted and authenticated by you by putting your initial on the balance of the said a/c. As per Branch record no such receipt was received either through cash or transfer entry. Credit voucher for such amount is also no in the record of the branch. Thus wilful damage to the bank is exposed by you.

6 SB A/c No. 2765/14 stands in the name of Pasupati Sengupta and Mr. Alakand Sengupta. The a/c. was introduced by you. In the said a/c. a cheque No. 909699 dated 27-10-84 for Rs. 367.50 fvg. LIC was paid by you as transfer entry on 7-11-84 where as the said cheque was never issued in the SB A/c. No. 2765/14 and as per Bank's record the cheque Book bearing No. 909691 to 909700 was never

issued to anybody but missing, it proves by the Branch's cheque Book issued register. Although the signature of the drawee on the said cheque is also not tallied differs as per their specimen signature Card. All these W/S were as per specimen signature card of SB A/c No. 2765/14 by you have passed for payment the said cheque. Cheque Book No. 911371 to 911380 was issued to you for your SB A/c No. 98/6 but from the said book a Cheque No. 911376 dated 11-3-85 for Rs. 2,000 was debited in SB a/c. No. 2765/14 on 11-3-85 and passed for Rs. 2,000 was debited in SB a/c No. 2765/14 on 11-3-85 and passed for payment by you. Another Ch. No. 911375 dated 15-3-85 for Rs. 361 was debited in SB a/c 2765/14 on 21-3-85 passed for payment by you where as signature of the drawer on the cheques does not tally as per Bank's record and the said debited cheque was issued to you for your SB a/c. No. 98/6 Ch. No. 911877 dated 7-10-85 for Rs. 369.80 was paid and SB a/c No. 2765/14 debited on 16-11-85 signature not tallied passed for payment by you. The said cheque leave from the cheque Book No. 911871 to 911880 was issued for your SB a/c. No. 98/6. Thus it shows you have defrauded the A/c and caused damage to the customer and thereby committing gross misconduct in terms of clause 19(5) (d) of the Bipartite Settlement. A withdrawal slip dated 6-11-81 for Rs. 1,000 was debited from the said A/c the payment was taken by you.

7. SB A/c. No 3943/21 stands in the name of Ashok Kumar and Balram Gupta.

The following cheque books were issued by the branch for your SB A/c 98/6 which were receipted by you, but from the said cheque Book cheque leaves utilised for debiting SB A/c. No. 3943/21 which were passed for payment by you after verifying the drawer's signature/not verifying signature, moreover signature of the drawer also does not tally as per the specimen signature card with the branch.

Cheque Book No. issued to you SB a/c. No. 98/6	Date of issue	Cheque leaves utilised by a/c holder of account No. 3943.
911401 to 911410	14-2-85	911406
912881 to 912890	28-5-85	912881
912471 to 912480	24-3-85	912477
911261 to 911270	24-11-85	911267

The following cheque leaves were utilised by you to debit SB a/c 3943/21 of Sri Ashok Kumar and Balram Gupta, where the signature of the A/c holder does not tally and even then passed for payment by you.

Date	Cheque No.	Amount
21-8-85	911406	1981.50
14-8-86	912881	807.35
14-8-86	912477	803.20
18-12-84	911267	486.50

Your above act is prejudicial to the interest of Bank also involving serious damage to customer, wilful damage to Bank's property for personal uses which must unmistakable terms indicate also an act which is prejudicial to the interest of the Bank causing loss to the bank, therefore, Bank for the above commission charges you for the gross misconduct under provision of 19.5(i) or Bipartite Settlement.

Your above stated acts constitute gross misconduct and clauses 19.5(d) and (j) of the Bipartite Settlement. Therefore, Bank without prejudice decided to initiate

disciplinary proceedings against you by holding an enquiry under the provisions of the above settlement only for those charges which are specifically denied by you, in the written statement submitted in defence to the charges of the Bank referred to above, within a period of 15 days from the date of receipt of the Chargesheet.

You are advised to either specifically deny the Charges levelled by the Bank or admit the charges.

In any case, if your reply in defence by the charges is not received within the above stipulated period, Bank shall deem that all the charges have been admitted by you and shall proceed with the course of action within the provision under Bipartite Settlement, without making any further reference to you in the matter.

Yours faithfully,  
Sd./- Illegible

(Asstt. General Manager)  
Disciplinary Authority."

19. Reply of the concerned workman to the Chargesheet Ext. M-2 is as follows :—

Dated 8-9-88

The Asstt. General Manager,  
(Disciplinary Authority)  
UCO Bank,  
Zonal Office,  
Patna.

Dear Sir,

Re : Chargesheet dated 30-7-88

Kindly refer to your letter No. Misc./Vig./88/273 dated 30-7-88. In this connection I wish to explain as under :—

1. Master Utam Choudhary (Minor) SB Alc. No. 2022 had attained majority at the time of withdrawal and as such withdrawal was allowed to him instead of his father and N. Guardian.
- (b) Smt Gayatri Devi had come personally and signed the withdrawal slip for Rs. 2,000. In view of the genuineness and prompt customer service I did not tally the signature with the AOF. The payment had been made to genuine a/c holder.
- (c) A near relative i.e. of Shyam Sunder Choudhary had come with a signed withdrawal slip along with the pass book. In view of the genuineness of the holder of the instrument payment was made to him. Some times the signature differ, but it is verified after finding its genuineness. I was not aware of the demise of Sri S. S. Choudhary nor it was recorded in the Bank's record.
- (d) Signatures were verified after assessing the genuineness the holder of the instrument.
2. Withdrawals were allowed in SB A/c. No. 2022 to the account holder/holder of the instrument after assessing the genuineness. Sri S. S. Choudhary was alive at the time of payment. I have no knowledge about his death.
3. Some entries were made erroneously in the SB A/c No. 3480 fvg. Poonam Chand Sharma. At a later date it was found that due to error excess payment had been made leading to some overdraft in the account. The account holder was informed and he adjusted the amount of overdraft.
4. Some wrong entries were made in SB A/c. Nos. 3784 and 4528 fvg. Sharda Malla and Rajendra Malla, and Radha Mohan Prasad. The wrong entries were corrected at a later stage when it was detected. Payments were allowed to the genuine persons. Sometimes, in view of customer service and in the interest of the bank, pay-in-slips were filled up by me.

5. Erroneously, some entries were made in the accounts of Sandip Kumar Bhattacharjee and Shufali Bhattacharjee. After the error came to my knowledge it was immediately corrected. There is no complaint from the side of the customer.
6. Sri Pasupati Sengupta and Mr. Alakananda Sengupta SB A/c. No. 2/65 are my old friends. They used to keep their cheque book with me. I had also got a cheque book issued in my name. Both the cheque books were in my personal custody. Whenever they came to the bank they used to take cheque book from me. Erroneously instead of filling up their cheque book from me. Erroneously instead of filling up their cheque book, they utilised my cheque Book. This was done not with any bad intention. The Cheques were passed for payment with no malafide intention, rather with good motive.
7. As narrated in para-6, Sri Ashok Kumar and Balram Gupta are also my old friends. They also used to leave their cheque book with me. Due to error they also utilised my cheque book instead of theirs. Payments were allowed in good faith. There has been no complaint from the side of account holder in regard to any irregularity.

During the period, Sri R. P. Jaiswal was the Asst. Manager of Joghani branch. After verbal instructions of Sri Jaiswal some payments were allowed. I apprehend, Sri Jaiswal might have played mischief due to union rivalry.

I am an old staff of the branch and have been instrumenting in bringing about Rs. 1 crore deposits. I have been discharging my duties to the best of my knowledge and ability. I have never put the bank to any sort of financial loss. There has been no complaint against me by any customer of the bank due to my promptness in customer service. However, in the light of the charges I shall be cautious in future and shall refrain from showing any sort of leniency.

The charges levelled against me are untrue to the facts. I do not accept the charges as levelled.

Thanking you,

Dated : 8-9-1988

Yours faithfully,

Sd./- A. P. Gupta,  
Special Asst. Joghani branch."

20. In reply marked Ext. M-2 the concerned workman practically admitted all the charges with some explanations. In support of his contention at the time of evidence no doubt he was able to give some declaration from Sarda Mallu, Gaitri Devi, Punam Chand Sharma, Sandeep Kr. Bhattacharjee, Farindra Pd. Acharya and Pasupati Sen stating that they have no grievances as regards their accounts and they are satisfied as regards operation of their respective accounts marked Exts. W-17 series. After considering the said materials on record and the registers of the bank the Enquiry Officer came to the conclusion that there is no proof that Uttam Choudhury attained majority at the relevant time nor his specimen signature was in the Bank for the verification and thereby irrespective of the attainment of the majority of Uttam Choudhury there was no reason to pass any cheque under signature of Uttam Choudhury by the concerned workman. It is also observed in the said report that specimen signature of the mother of the minor too varied with reference to the signatures remained in the office. It is a fact that though S. S. Choudhury died on January, 1982 that was not informed in the Bank but the fact remains that the signature appear to be the signature of S. S. Choudhury obviously did not tally with the signature maintained in the office. So, it was held that charge No. 1 was established

and from the report of the Enquiry Officer Ext. M-4 it appears that something happened as regards charge No. 2 and there was repetition of the said negligence and after disregard to the operational procedures of the Bank by the concerned workman which tantamounted to be the violation of the bank's rules leading to the establishment of the charge. Furthermore, this report goes to show that withdrawal of Rs. 7,000 relating to S/B A/c. No. 3480 was passed pursuant to non-existent deposit of Rs. 5,000 which was shown to be deposited on 10-7-86 though it was holiday. The matter did not end there. It was corrected after 2-1/2 months i.e. on 20-9-86. Accordingly, this act was considered to be arbitrary and tampering of the Bank's documents. It was also observed and held in the enquiry that there was unauthorised transfer of funds from S/B A/c. No. 601/3 to A/c. No. 3480 and 3943 on 2-8-86 though the debit of 2-8-86 in Account No. 601/3 was made good on 30th September, 1986. Furthermore, it was revealed that account holders used to stay long away from Joghani at Dhara in Nepal and that the account was operated committing breach of trust to the depositor. Another charge was found to be established as regards adhoc credit of Rs. 6,200 without having any supporting voucher but simply altering the balance in the said account No. 3184 only on 2-1-86 after lapse of 1 1/2 years and there was withdrawal from the said account on 14-8-86 and 18-8-86 to the tune of Rs. 16,145 in total which was deposited later on. As regards charge No. 5 relating to a sum of Rs. 7,100 the office record was altered and tampered which was highly risky to the bank of course the account was of Sri S. K. Bhattacharjee who did not make any grievance against the concerned workman but that itself cannot wipe out the irregularity that has been done by the concerned workman. It was also established that various cheque books used to remain with him and those were handled by him. Cropping up various irregularities and in course of operation the comparison of signature etc. were not made and thereby a gross negligence and irregularities were performed by the chargesheeted employee who is the concerned workman in the instant reference.

21. I have carefully perused and I have applied my mind with all leniency but I cannot ignore the said acts to be mere accidental or having no knowledge of the concerned workman nor it appears to me to be technical one.

22. Rather it shows absolute callousness and glaring examples of ignoring the Bank's rules totally considering the Bank property to be his own property which was urged by the management.

23. Therefore, I have no hesitation to hold that the enquiry being held properly and fairly was justified to hold the concerned workman to be guilty of the charges levelled against him irrespective of his bright career or services life which will be discussed later on. In view of the discussions made above I do not find any reason to interfere with the findings of the enquiry authority holding the concerned workman to be guilty of the charges levelled against him and also I do not find any wrong by disallowing the appeal preferred against that finding before the Appellate authority confirming the decision. I have carefully perused the report or the enquiry officer as well as finding of the appellate authority and I concur with the finding and thus it is held that the concerned workman Shri A. P. Gupta is liable for the commission of the irregularities as discussed and pointed out earlier and he should be imposed with penalty. However, we are to discuss later on about the extent of such penalty or punishment.

24. The next point which is vital before the Tribunal what punishment has to be awarded for commission of such serious irregularities and which appear to be intentional and outcome of callousness of workman who had such a good reputation in service in the past.

25. Already it has been observed that such bunches of irregularities cannot be considered to be slip of pen or due to inadvertence or through oversight. But it can be firmly asserted that the concerned workman reached to such stage which prompted him to ignore any norms of the Bank's rules for the reasons known to him though fortunately no financial loss or damage was caused to the pro-

erty and reputation of the Bank. But the trend of the work of the concerned workman reveals that at any point of time there was such chances which may lead the Bank to suffer a loss of its property as well as its reputation. It is a fact that the concerned workman has received appreciation from the authority concerned for his work vide Ext. W-13, W-14, W-15. In this premises I cannot check my temptation to point out that if a workman is entitled to get an appreciation for his good job he must be condemned if any bad job comes out from his activity detrimental to the interest of the Bank concerned. No doubt the acts and the irregularities as discussed and pointed out and revealed in course of enquiry appear to be severe one and there was chance of loss of reputation and property to the Bank if it was not detected within a short period.

26. So, I am of the opinion that he cannot be dealt with under Sections 2(oo) and 25-F of the I. D. Act nor those are applicable in the present case rather negligence, non-application of mind, mistrust etc. are established and those are practically admitted by the concerned workman Shri A. P. Gupta.

27. Of course, it is settled principle of law that confession of guilt itself cannot establish a charge and the same must be corroborated by independent materials. In the instant proceeding there are ample materials which are sufficient to corroborate Admission or confession whatever it may be said, made by the concerned workman Shri A. P. Gupta relating to the charges levelled against him. It was argued by Shri B. Prasad, the learned representative on behalf of the workman that these irregularities should be considered as minor misconduct as per clause 19.7 of Chapter 9 of the Bipartite Settlement between Banking Companies and their workmen. But from the side of the Bank it has been argued by the learned Law Officer of the management that under clause 19.5 irregularities and act of the concerned workman should be considered as "Gross misconduct."

28. I have applied my mind and I have gone through clause 19.5 and 19.7 of the said settlement and I am of the opinion that the nature of the irregularities and acts done by the concerned workman cannot be considered to be minor misconducts under clause 19.7 but in my opinion, that should be considered as gross misconduct under clause 19.5 holding that there was wilful damage or attempt to cause damage to the property of the Bank or any of its customers under sub-clause (d) of the said clause and doing an Act prejudicial to the interest of the Bank or gross negligence or negligence involving or likely to be involved Bank in serious loss under sub-clause (j) of clause 19.5. It will be hard to consider the same to be only neglect of work or negligence in performing the duties under sub-clause (c) of clause 19.7 as argued by Shri Prasad for the workman. In that case I am reluctant to accept that the employee or the concerned workman should be dealt with under clause 19.8 for the purpose of imposing penalty as canvassed by Shri Prasad.

9. In this context it is pertinent to mention that this part of argument clearly leads to a stage that the concerned workman attempted to commit a misconduct but he argued it to be minor misconduct.

30. But in view of the discussions made above I am with foundation to hold as it had been held by the Enquiry Officer that it was a gross misconduct and his punishment was properly dealt with under clause 19.6 under the said settlement. No doubt, in clause 19.6 the first punishment is the dismissal of the employee without notice which is the maximum punishment though it was wrongly stated as clause 19.6 which is no doubt but a typographical mistake. In the matter of inflicting of the punishment my attention was drawn by Sri Prasad to clause 19.12 of the said settlement and sub-clause (c) in which it is clearly stated that in awarding punishment by way of disciplinary action the authority concerned shall take into account the gravity of the misconduct, the previous record, if any, of the employee and any other aggravating or extenuating circumstances, that may exist.

31. So it would be unjust if the punishment be awarded by the disciplinary authority only taking into consideration of the gravity of the misconduct without considering his past record and any other circumstances referred to in the instant clause. Already it has been pointed out that Ext. W-13, W-14 and W-15 clearly reveal the appreciation of the workman concerned Shri A. P. Gupta regarding his work from the higher officials of the management concerned. At the same time though there were several irregularities but actually none of the customers of the said Bank suffered any financial or any kind of loss and they have come forward to state such facts voluntarily in writing nor it has been established by the management that there was any actual loss or damage to the property or the reputation of the Bank.

32. So I think that punishment should be awarded for such misconduct though it was gross in nature not only keeping in mind the misconduct caused by the concerned workman itself but with the background of other two facts which have been mentioned in sub-clause (c) under clause 19.12 of the Bipartite Settlement between Banking Companies and their workmen.

33. We should not shut our eyes in the matter of imposition of sentence when the enquiry authority takes steps to impose the highest punishment if there is some grounds to award some relief to the said workman who was appreciated for his work in the past giving a chance for his amendment specially when no loss or damage has been caused to the property or the reputation of the Bank itself.

34. For this purpose the Tribunal invokes power under Section 11-A of the I. D. Act, 1947 where it is stated that if the Tribunal be not satisfied about the order or discharge or dismissal even in that case he can give such other relief to the workman including the awarding of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require on such terms and conditions as it may deem fit.

35. After applying my judicial mind along with the principles enunciated in the case reported in S.C.L.J. 1973 Vol. 10 in a case—the workmen of Fire Stone Tyre and Rubber Co. versus the management and others at page 159. I am of the opinion that the disciplinary authority was too harsh in imposing punishment by dismissing such an old employee who was appreciated by the high official of the management when there was no loss or damage of the property of the Bank and atleast one chance should have been given to amend himself with caution without dismissing him outright. Of course, I am not forgetful that the Bipartite agreement to some extent stands in the way to the enquiry authority to deal with the matter in other way but in his Tribunal I am of the opinion that without becoming so harsh in awarding some punishment to him in the following manner after setting aside the order of dismissal which is the one part of the reference can be disposed off in the following relief to meet the justice.

36. I think that if the order of dismissal of the concerned workman be set aside and he be allowed to be reinstated in his old post with the following observation and terms and conditions that will meet the justice for all purposes.

37. Accordingly it is held that I am not inclined to sustain the order of dismissal of the concerned workman Shri A. P. Gupta and so it is set aside. The management is directed to reinstate him in the same post within one month from the date of publication of the Award with 50% of the back wages from the date of his dismissal till the date of his reinstatement, of course, not giving any increment during his idle period and he should be posted in the same rank in which he was, without disturbing his position in the gradation list or without depriving his future benefits in his service but not posting him in the same branch of the Bank where he was with liberty, to post him any place as per choice of the Bank management. It is further directed back wages for the idle period as

granted in favour of the concerned workman should be paid within 3 months from the date of his reinstatement without any interest thereon.

38. No cost is awarded to either of the parties.  
This is my Award.

D. K. NAYAK, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.प्र. 658.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लिमि. के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-20012/47/93-आईआर (कोल-1)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 658.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th February, 1995.

[No 1-20012/47/93-IR (IR (Coal-I))  
BRAJ MOHAN, Desk Officer.

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT DHANBAD

PRESENT :

D. K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

REFERENCE NO. 203 OF 93

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Koyala Bhawan, Dhanbad and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.  
State : Bihar Industry : Coal.

Dated, Dhanbad, the 7th February, 1995

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/47/93-L.R. (Coal-I), dated, the 30th November, 1993.

#### THE SCHEDULE

"Whether the demand of the Union from the management of M/s. B.C.C.L. Koyala Bhawan, Dhanbad for promotion of S/Shri R. C. Mishra and Mishri

Lal to the post of Special Grade Technical and Supervisory Grade 'A' with retrospective effect is justified? If not, to what relief the workman are entitled?"

2. In this reference both the parties appeared but only the workmen filed their Written Statement. Thereafter the case was fixed for filing W.S. of the management. I find from the record that both the parties appeared and filed a memorandum of settlement on 1-7-94 and the Award could not be passed as the post of the Presiding Officer in this Tribunal was lying vacant.

3. Again the case file was put up on 7-2-95 before me and I heard both the parties on the said memorandum of settlement. I have gone through the said memorandum of settlement and I find that the terms contained therein are fair, proper, beneficial and legal one. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

D. K. NAYAK, Presiding Officer

Form H

#### MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Representing  
Management.

Shri U. K. Jha,

Dy. Chief Pers. Manager (NEE).

Representing Union/Employees

1. Shri D. Mukherjee,  
Secy. Bihar Colly.  
Kamgar Union.
2. Shri R. C. Mishra,  
Sr. Legal Assistant.
3. Shri Mishri Lal,  
Sr. Legal Assistant.

#### SHORT RECITAL OF THE CASE

S/Shri R. C. Mishra and Mishri Lal both Sr. Legal Assistants raised an Industrial Dispute before ALC(C), Dhanbad 4 through BCKU Union demanding their placement as Legal Inspector in Tech. Gr. "B" from the date they were placed as Sr. Legal Assistant in Clerical Gr. I w.e.f. 1-8-90. Their demands based on the facts that they had applied against the Departmental circular for selection of Legal Assistant in Special Gr./Supervisory grade in Tech. Gr. 'A' and on their qualifying in the written test they were posted in the Legal Department and subsequently after 6 months they were placed as Legal Inspector/Legal Assistant in Legal Department. Their demand is also that they had qualified in the written test and subsequent interview/test by the Selection Committee and therefore they should have been placed as Legal Inspector in Tech. Gr. 'B' as has been offered to others.

The dispute failed in conciliation and the matter was referred to Ministry from where the dispute has been referred to CGIT No. 2 being of. No. 203/93 for adjudication.

The details of the dispute has been discussed with the concerned employees and their demand has been considered sympathetically by the Management and it has been decided that the dispute should be settled as per the following terms :—

1. It is agreed that S/Shri R. C. Mishra and Mishri Lal will be placed in Tech. Gr. "B" as Legal Inspector w.e.f. the date they raised the dispute i.e. 13-3-92 with notional seniority and notional fixation only no financial benefit. However, they will get financial benefit from the date of signing of this settlement.
2. That there will be no dispute and no representation from the employees in the above matter.
3. This settles the dispute in full and final.

#### SIGNATURE OF THE PARTIES

MANAGEMENT

U. K. JHA, Dy Chief pers. Manager (NEE)

Witness :

1. Sd/-
2. Sd/-

## UNION/EMPLOYEES

1. D. MUKHERJEE, Secy. Bihar Colly. Kamgar Union

2. R. C. MISHRA, Sr. Legal Assistant

3. MISHRI LAL, Sr. Legal Assistant

Dated : 20-6-94.

No. BCCL/PA-V/ID/RC MISHRA/92/6253-56.

Copy to :

1. The Asst. Labour Commissioner(C), Dhanbad-IV.
2. Regional Labour Commissioner(C), Dhanbad.
3. Central Labour Commissioner(C), New Delhi.
4. Secretary to Govt. of India  
Ministry of Labour, New Delhi.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.प्रा. 659.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में, भारत कोकिंग कोल लिमि. के प्रबन्धनत्व के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 फरवरी, को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/65/88-डी-4(ए)/आर्डर (कोल-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 659.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-2-95.

[No. L-20012/65/88-DIV(A)/IR(Coal-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT DHANBAD

## PRESENT

Shri D. K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 22 OF 1992

## PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri Mangat Dusadh, the concerned workman.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.  
STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 8th February, 1995

## AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(65)/88-D.4(A)/I.R. (Coal-I), dated, the 21st April, 1992.

## SCHEDULE

"Whether the demand of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that Shri Mangat Dusadh, be regularised as Assistant Store Keeper in Clerical Gr. III from the date he was holding charge is justified ? If so, to what relief is the workman entitled ?"

2. In this case both the parties appeared but only the workman filed its Written Statement. Subsequently, when the case was fixed for Written Statement of the management, both the parties appeared before me and filed a compromise petition under their signature. I heard both the parties on the said compromise petition and I find that the terms of the compromise petition are fair, proper, beneficial and legal one. Accordingly I accept the said compromise petition and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

D. K. NAYAK, Presiding Officer.

## ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Tribunal No. 2,

REFERENCE NO : 22/92

Employers in relation to the management of Sudamdih Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

And

Their Workmen

## PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully sheweth :—

1. That the Central Government by Notification No. L-20012/65/88-D-IV(A)/IR (Coal-I) dated 21-4-1992 was pleased to make the present reference to the Hon'ble Tribunal for adjudication on the issue contained in the Schedule of reference which is reproduced below :—

## SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that Shri Mangal Dusadh be regularised as Assistant Store Keeper in Clerical Grade III from the date he was holding the charge is justified ? If so, to what relief the workman is entitled ?"

2. That the dispute was amicably settled between the parties to the above reference on the following terms—

## TERMS OF SETTLEMENT

- (a) That Shri Mangal Dusadh, Shale Picker, in Category I will be placed in Category IV as Tyndel (Stores) with effect from the date of reference i.e. 21-4-1992.
- (b) That the concerned workman will not be entitled to any other benefit and all his claim arising out of the dispute will be deemed to have been finally settled without any claim of any kind in future.
- (c) That the concerned workman's scale of pay will be fixed taking into consideration his placement in Category IV with effect from 21-4-1992 within 30 days from the date of publication of this Award.

3. That in view of the aforesaid settlement there remains no further dispute for adjudication.

Under the facts and circumstances stated above, the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen :

(G. D. Pandey)

Vice President,

R.C.M.C.

Witness :

1.

1.

Sd/-

For the Employers.  
Chief General Manager,  
Sudamdih Area  
B.C.C.L.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.प्रा. 660.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/20/93-आईआर(बी-1)]

पी. जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 660.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-2-1995.

[No. L-12012/93-IR(B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(112)/1993

## BETWEEN

Shri Raghunath Singh Maliha, Messenger-cum-Cleaner, represented through the General Secretary, Durg Rajnandgaon Gramin Workers Organisation, Old Russian Block, Bhilai, Distt. Durg (MP)-490006.

## AND

The Chairman, Durg Rajnandgaon Gramin Bank, M.P. Housing Shopping Centre, Rajnandgaon-491441.

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES :

For Workman Shri R. D. Rao.

For Management : Shri Sanjay Kadam.

INDUSTRY : Banking. DISTRICT : Durg (MP).

## AWARD

Dated, January 25, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/20/93-IR(B-I) dated 8-6-1993 for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank in terminating the services of Shri Raghunath Singh Maliha, Messenger-cum-Cleaner, w.e.f. 6-11-90 is legal and justified? If not to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. Parties have not filed the statement of claim or the written statement. As per terms of compromise the management has agreed to give fresh appointment to the workman. The settlement is verified and it is just and proper. Following are the terms of settlement :—

## TERMS OF SETTLEMENT

1. That the second party has agreed to give fresh appointment to Shri Raghunath Singh Maliha as Regular part-time Messenger and the first party has agreed to accept his fresh appointment. The terms and conditions of fresh appointment are annexed with this compromise application as Annexure-A.

2. That in view of the above compromise, the party relinquishes the claim of Shri Raghunath Singh Maliha regarding reinstatement and back wages and does not press the same.
3. That the parties will bear thereon costs.
4. It is, therefore, prayed that the award may kindly be passed in terms of above compromise and the case may be closed at this stage.
3. In view of the above settlement no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.प्रा. 661.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/38/93-आईआर(बी-1)]

पी. जे. माइकल

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 661.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-2-1995.

[No. L-12012/38/93-IR(B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(115)/1993

## BETWEEN

Shri Bhesraj Kumar Sahu represented through the General Secretary, Durg Rajnandgaon Gramin Bank Workers Organisation, Old Russian Block, Sector-6, Bhilai, Distt. Durg (MP).

## AND

The Chairman, Durg Rajnandgaon Gramin Bank, M.P. Housing Shopping Centre, Rajnandgaon (MP).

PRESIDED IN : Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES :

For Workman : Shri R. D. Rao.

For Management : Shri Sanjay Kadam.

INDUSTRY : Banking. DISTRICT : Durg (MP).

## AWARD

Dated, January 25, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/38/93-IR(B-I) dated 8-6-1993 for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank in terminating the services of Shri Bhesraj Kumar Sahu, Messenger, w.e.f. 5-12-1990 is legal and justified? If not, to what

relief the workman is entitled to and from which date?"

2. Parties have not filed the statement of claim or the written statement. As per terms of compromise the management has agreed to give fresh appointment to the workman. The settlement is verified and it is just and proper. Following are the terms of settlement:—

#### TERMS OF SETTLEMENT

1. That the second party has agreed to give fresh appointment to Shri Bheshaj Kumar Sahu as regular Part-time messenger and the first party has agreed to accept his fresh appointment. The terms and conditions of fresh appointment are annexed with this compromise application as annexure-A.
  2. That the order of fresh appointment will be issued to Shri Bheshaj Kumar Sahu within one month from the date of order of this court.
  3. That in view of the above compromise, the first party relinquishes the claim of Shri Bheshaj Kumar Sahu regarding reinstatement and back wages and does not press the same.
  4. That the parties will bear thereon costs.
  5. It is, therefore, prayed that the award may kindly be passed in terms of above compromise and the case may be closed at this stage.
3. In view of the above settlement, no dispute award is passed without any order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer  
नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का. आ. 662.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/21/93-आईआर/(बी. I)]  
पी. जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 662.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-2-1995.

[No. L-12012/21/93-IR(B-I)]  
P. J. MICHAEL, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)  
Case Ref. No. CGIT/LC(R)(113)/1993

#### BETWEEN

Shri Yog Raj represented through the General Secretary,  
Durg Rajnandgaon Gramin Bank Workers Organi-  
sation, Old Russian Block, Bhilai, District Durg  
(MP).

#### AND

The Chairman, Durg Rajnandgaon Gramin Bank, M.P.  
Housing Shopping Centre, Rajnandgaon (MP).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES:

For Workman: Shri R. D. Rao.

For Management: Shri Sanjay Kadam.

INDUSTRY: Banking. DISTRICT: Durg (MP).

#### AWARD

Dated, January 25, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/21/93-IR(B-I) dated 8-6-1993 for adjudication of the following industrial dispute:—

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank in terminating the services of Shri Yog Raj Sahu S/o Shri Dula Ram Sahu, Messenger-cum-Cleaner with effect from 8-3-90 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. Parties have not filed the statement of claim or the written statement. As per terms of compromise the management has agreed to give fresh appointment to the workman. The settlement is verified and it is just and proper. Following are the terms of settlement:—

#### TERMS OF SETTLEMENT

1. That the second party has agreed to give fresh appointment to Shri Yog Raj Sahu as Regular part-time Messenger and the first party has agreed to accept his fresh appointment. The terms and conditions of fresh appointment are annexed with this compromise application as Annexure-A.
  2. That the order of fresh appointment will be issued to Shri Yog Raj Sahu within one month from the date of order of this court.
  3. That in view of the above compromise, the first party relinquishes the claim of Shri Yog Raj Sahu regarding reinstatement and back wages and does not press the same.
  4. That the parties will bear thereon costs.
  5. It is, therefore, prayed that the award may kindly be passed in terms of above compromise and the case may be closed at this stage.
3. In view of the above settlement no dispute award is passed without any order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का. आ. 663.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/39/93-आईआर/बी. I)]  
पी. जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 663.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-2-95.

[No. L-12012/39/93-IR(B-I)]  
P. J. MICHAEL, Desk Officer



## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(116)/1993

## BETWEEN

Shri Net Ram Verma, represented through the General  
Secretary, Durg Rajnandgaon Gramin Bank Workers  
Organisation, Old Russian Block, Sector-6, Bhilai,  
District Durg (MP).

## AND

The Chairman, Durg Rajnandgaon Gramin Bank, M.P.  
Housing Shopping Centre, Rajnandgaon (MP).  
PRESIDED IN: By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES:

For Workman: Shri R. D. Rao.

For Management: Shri Sanjay Kadam.

INDUSTRY: Banking.

DISTRICT: Durg (MP).

## AWARD

Dated, January 25, 1995

This is a reference made by the Central Government in the  
Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/39/93-  
IR(B-I) dated 8-6-1993 for adjudication of the following indus-  
trial dispute:—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Durg Raj-  
nandgaon Gramin Bank in terminating the services  
of Shri Net Ram Verma, Messenger-cum-Cleaner  
w.e.f. 1-12-90 is legal and justified? If not, to  
what relief the workman is entitled to and from  
which date?"

2. Parties have not filed the statement of claim or the  
written statement. As per terms of compromise the manage-  
ment has agreed to give fresh appointment to the workman.  
The settlement is verified and it is just and proper. Follow-  
ing are the terms of settlement:—

## TERMS OF SETTLEMENT

1. That the second party has agreed to give fresh ap-  
pointment to Shri Net Ram Verma as regular part-  
time Messenger and the first party has agreed to  
accept his fresh appointment. The terms and con-  
ditions of fresh appointment are annexed with this  
compromise application as Annexure-A.
2. That the order of fresh appointment will be issued  
to Shri Net Ram Verma within one month from the  
date of order of this court.
3. That in view of the above compromise, the first  
party relinquishes the claim of Net Ram Verma re-  
garding reinstatement and back wages and does not  
press the same.
4. That the parties will bear their own costs.
5. It is, therefore, prayed that the award may kindly  
be passed in terms of above compromise and the  
case may be closed at this stage.
3. In view of the above settlement, no dispute is passed  
Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.आ. 664.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947  
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार  
भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और  
453 GI/95—8

उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद  
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट  
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95  
का प्राप्त हुआ था।

[स. एल-12012/264/91-आईआर(बी. III)/बी. I.]

पी.जे. माइकल डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 664.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the Award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in  
the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of State Bank of India and their workmen,  
which was received by the Central Government on the  
13.2.95.

[No. L-12012/264/91-IR(B-III)/B-I]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(224)/1991

## BETWEEN

Shri Anand Rao Shalikram Tekam, Messenger, C/o Shri  
Ramesh Kirana Stores, Indira Nagar, Behind T.B.  
Ward. Ajni, Nagpur-441001 (MS).

## AND

The Dy. General Manager, State Bank of India, Kings-  
way, Nagpur-441001 (MS).

PRESIDED IN: By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES.

For Workman: Workman himself.

For Management: Shri D. Sachdeva, Advocate.

INDUSTRY: Banking.

DISTRICT: Nagpur (MS).

## AWARD

Dated, January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the  
Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/264/  
91-IR.B.III, dated 29-11-1991 for adjudication of the follow-  
ing industrial dispute:—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank  
of India in terminating the services of Shri Anand Rao  
Shalikram Tekam, Messenger, w.e.f. 5-2-91 is jus-  
tified? If not, to what relief he is entitled to?"

2. Parties have filed the statement of claim and the written  
statement. The case was posted for filing the documents.  
However, an application was filed on 23-3-94 by the workman  
to drop the proceedings in the case. It is alleged by the  
workman in the application that he has received the employ-  
ment and he does not want to press the claim under refer-  
ence. On 12-1-95 the case was posted for the verification  
of the application filed by the workman and the workman  
appeared and prayed that the proceedings be dropped. The  
workman is already reinstated by the management and he  
has foregone the back wages.

3. In view of the aforesaid circumstances, no dispute award  
is hereby passed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

का.आ. 665.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर (एम.पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या: एल 29011/13/91-आई आर (विविध)]  
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th February, 1995

S.O. 665.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (MP) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-1995.

[No. I-29011/13/91-IR(Misc.)]  
B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)  
Case Ref. No. CGIT/LC(R)(167)/1991

#### BETWEEN

Shri Gulab Lezmanji Shende, Driller and three others, represented through the Secretary, Maharashtra State Mining Corporation Employees Union, C/o Shri M. N. Kishsagar, Plot No. 139, Abhyankar Nagar Nagpur-10(MS).

#### AND

The Chairman-cum-Managing Director, Maharashtra State Mining Corporation Ltd., 5, Abhyankar Nagar, Nagpur-10 (MS).

PRESIDED IN : Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Workman : None.

For Management : Shri V. S. Verma.

INDUSTRY : Mining. DISTRICT : Nagpur (MS).

#### AWARD

Dated, January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-29011/13/91-IR(Misc.), dated 26-9-91/3-10-91 for adjudication of the following industrial dispute :—

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Maharashtra State Mining Corporation Limited, Nagpur for not regularising the services of (1) Shri Gulab Lazmanji Shende, Driller, (2) Shri Khumlal Jattilalji Raut, Driller, (3) Shri Subhesh Singh Shekhuji Dhawade, Drilling Helper and (4) Shri Shriram Asaramji Halba, Drilling Helper, in the regular cadre is justified. If not, so then what relief the workman are entitled to?"

2. The workmen or the management have not filed the statement of claim and the written statement. Notice to the workmen was sent for filing the statement of claim on

10-10-91, 10-12-91, 28-1-92, 2-4-92 and 16-8-94. The management also informed the workman about the date of hearing. In spite the repeated notices to the workman to file the statement of claim workmen failed to file the statement of claim.

3. Consequently, it is clear that the workmen are not interested in pursuing their claim. No dispute award is passed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 666.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओरिएण्टल इन्स्योरेंस कंपनी लि. के प्रबन्धन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17011/8/90-आई आर.बी.-2]  
बी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 666.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Oriental Insurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 16-2-95.

[No. L-17011/8/90-IR(B.II)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

#### PRESENT :

Shri P. K. Tripathy, M.A.L.L.B.,  
Presiding Officer, Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 27 of 1990

(Central)

Dated, Bhubaneswar, the 30th January, 1995

#### BETWEEN :

The management of Oriental Insurance Co. Ltd.,

Parmar Building, Kachari Road, Rourkela-12.

First party-mangement.

AND

Versus

Their workman Sri C. S. Murty,  
C/o Champion Tailors,  
Kacheri Road, Rourkela-12.

The Oriental Insurance Co. Ltd . . . O.P.

1. O.P. begs to state as under :

1. That this case was filed by Mr. C.S. Murthy (Petitioner) against this management for getting appointment as a Sub-staff in this organisation.
2. That Mr. Murthy has already been appointed as a Sub Staff with effect from 14-02-94 with this organisation and therefore, the matter has been settled.
3. Further, this managements begs to inform the court that the confirmation letter of Mr. Murthy has been sent to our Divisional Office, Rourkela and will be handed over to him soon after the withdrawal of this case.
4. Since the dispute no more exists both the parties request the court to kindly pass orders in favour of closure of the case.

(R. N. DAS),  
Assistant Manager

For Oriental Insurance Co. Ltd.  
Dt. 24-1-95

### IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

Ref :—

I.D. Case No. 27/90(C)

Name of parties

M/s. Oriental Insurance Co. Ltd., Employer.

-Versus-

Shri C. S. Murty (Workman)

Short recital of the case :—

- (1) Shri Chidambaram Subramaniam Murty (hereinafter referred to as C. S. Murty), worked in the office of Branch Manager, Oriental Insurance Co. Ltd., Rourkela (later upgraded to Div. Office) as a "Water boy" from 8-2-74 to 31-10-79 when he left the job after tendering resignation. He was re-employed as a daily wager on Rs. 12/- per day from 1-11-83 and he continued to work intermittently till 4-2-85.
- (2) Shri Murty raised an Industrial dispute on 20-7-89 after a long gap of 4 years alleging illegal and unjust attitude of the management in refusing him a job on regular/permanent basis and employing his junior on regular basis as Sub-staff.

. . . Second party-workman.

### APPEARANCES :

Sri R. N. Das, Assistant Manager—For the first party management.

Shri C. S. Murty.—The second party workman himself.

### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-17011/8/90-IR.B-I/B-II dated 10-7-90 :—

"Whether the action of the management of Oriental Insurance Co. Ltd. Parmar Building, Kacheri Road, Rourkela-12 in (1) refusing employment to Shri C.S. Murthy w.e.f. February, 1985 and also (2) ignoring the claim of Shri Murthy for employment as sub-staff while making fresh recruitment in the year 1987, relief the workman is entitled to ?"

2. At the stage of hearing (on 24-1-95), the workman and so also the representative of the management by filing a joint petition prayed to pass an award in terms of the settlement filed earlier.

On persual of the terms of settlement, it appear that the second party-workman has since been engaged as a sub-staff in the organisation of the first party. The terms of the settlement are readover and explained to the parties to which they admit to be true and correct. The terms being fair are recorded. In view of the above, an award is passed in terms of the settlement which do form part of the Award.

Dictated & corrected by me.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer

IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER,  
INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

I.D. Case No. 27/90(c)

C. S. Murthy

. . . Petitioner

(3) Management of the Co. regretted its inability to provide a job to Shri Murty on the ground that his services were never terminated and it was the workman himself who resigned his job. Despite objection raised by the 1st party conciliation proceedings were initiated. However after the conciliation proceedings ended in a failure, the Asstt. Labour Commissioner concerned referred the matter to Secretary, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi, who in turn referred the matter to the Industrial Tribunal, Bhubaneswar for adjudication and settlement in accordance with Sub-section 2-A of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947.

(5) In the written statement filed by the Management, it expressed its willingness to consider the case of Shri Murty for appointment against the post of Sub-staff subject to availability of vacancy and his being found suitable in all respects.

(6) After settlement of issues, the Hon'ble Court fixed 6-11-92 for hearing when the workman and the management prayed to the Court for time to allow them to compromise as Shri Murty agreed to the terms offered by the Company and also gave his acquiescence to waive off his demand for appointment with retrospective effect. The management agreed for a compromise both as matter of compassion for the workman and for ensuring harmony between the workman and the Management.

#### Terms of Settlement :

The Management agreed to offer Shri Murty (Workman) an appointment as a "Sub-Staff" subject to availability of a vacancy and his being found suitable as regards his age, qualification, and medical fitness. Shri Murty accepted the offer and agreed to waive off his demand for retrospective appointment.

#### Witness :—

1. ....  
(Er : D. K. PATNAIK),  
Surveyor & Loss Assessor,

2. ....  
(Rajendra Narayan Dass)

A.O

Oriental Insurance Co. Ltd.  
R.O. Bhubaneswar

Signature of the Parties.  
For the Oriental Insurance Co. Ltd.  
Regional Office, Bhubaneswar  
Asstt. Manager

1. For Oriental Insurance Co. Ltd.,  
2. Workman/Petitioner.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 667—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/22/92-आईआर (बी-1)]  
पी.जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 667.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-2-95.

[No. L-12011/22/92-IR(B.I)]  
P. J. MICHAEL, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(168/1992.

#### BETWEEN :

The Secretary Reserve Bank Employees  
Association, Arun Bhawan, Temple  
Bazar, Sitabuldi, Nagpur(MS)-  
440 012.

#### AND

The Manager, Reserve Bank of India,  
Nagpur(MS)-440 001.

#### PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Union : Shri Tare.

For Management : Shri Vinchurni.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur(MS)

#### AWARD

Dated. January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its

Notification No. L-12011/22/92-IR.B.III, dated 31-7-1992 for adjudication of the following industrial dispute :—

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Nagpur, in issuing circular restricting the number of occasions of availing leave from ten to seven times in a year by workmen is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?”

2. Management and the workmen have not filed the statement of claim and the written statement and it is alleged by the management on 15-11-94 that the matter is under negotiations for the mutual settlement. The case was posted for filing the settlement on 11-1-1995.

3. Parties did not appear on 11-1-1995. It appears that the minor dispute between the parties is settled out of Court. Consequently, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

क्र.सं. 668.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/40/93-आईआर(वोआई)]

पी. जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 668.—In pursuance of Section 17 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-2-95.

[No. L-12012/40/93-IR(B.I.)]  
P. J. MICHAEL, Desk Officer

### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(79)/1993

BETWEEN :

Shri S. Prabhakar, Coin Note Examiner Grade II, represented through the Assistant Secretary, Reserve Bank of India Employees Association, C/o Reserve Bank of India, Nagpur (MS)-400 023.

And

The Manager, Reserve Bank of India, Nagpur (MS)-400 023.

PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman : None.

For Management : None.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur(MS)

### AWARD

Dated, January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/40/93-IR.D.I dated 7-4-1993, for adjudication of the following industrial dispute :—

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Nagpur, in refusing payment of difference of Railway fare performed by Shri S. Prabhakar, Coin Note Examiner Grade II from Bombay to Nagpur on 7-2-92 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. The admitted facts of the case are that Shri S. Prabhakar, the workman, while performing the remittance duty to Government Mint Bombay accompanied 600 boxes from 5-2-92 to 8-2-92; that the workman was entitled to travel in 1st Class while travelling by train. It is also not in dispute that the workman performed the official return journey from Bombay to Nagpur on 7-2-92 in IInd Class by Bombay-Howrah Mail.

3. The workman has not obtained no accommodation certificate from the relevant Railway

Authorities. In terms of Bank Circular dated 24-11-76 employee is required to produce no accommodation certificate or LCC. Consequently, it cannot be said that the accommodation in 1st Class in the train was not available to the workman. In these circumstances, it is not established as per requirement of the Rule that there was no accommodation of 1st Class on the day of journey on 7-2-92. In this back drop the action of the management in refusing the payment of difference of railway fare between 1st Class and 2nd Class journey performed by the workman from Bombay to Nagpur on 7-2-92 is as per rules and justified.

4. The workman has not led any evidence to show that even without the no accommodation certificate or LCC as required by the Bank Circular dated 24-11-76 the certificate issued by the Mint Authorities for the non-availability of the accommodation in 1st Class is valid and acceptable.

5. Consequently, the action of the management with regard to the terms of reference is justified and the reference is answered in favour of the management. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 669.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ जनरल मैनेजर, टैलीकॉम फैक्टरी, जबलपुर के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-40012/121/93-आई आर (डी यू)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 669.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chief General Manager Telecom Factory, Jabalpur and their workmen, which was received by the Central Government on 13th February, 1995.

[No. L-40012/121/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(208)/1993.

BETWEEN

Shri Suneshwar Prasad, Quarter No. 242,  
D. Type, Telecom Factory, Jabalpur  
(MP)-482001.

AND

The Chief General Manager, Telecom Factory,  
Jabalpur (MP).

PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman : Workman himself.

For Management : Shri B. De' Silva, Advocate.

INDUSTRY : Telecom

DISTRICT :

Jabalpur (MP).

AWARD

Dated : February 1, 1995.

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/121/93 dated 30-9-1993 for adjudication of the following industrial dispute:—

## THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chief General Manager, Telecom Factory, Jabalpur in terminating the services of Shri Suneshwar Prasad, Ex-Machine Sheter-cum-Operator w.e.f. 8-10-1991 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. The case of the management is that the workman who was employed as Machine Sheter-cum-Operator together with some co-workers instigated a crowd of about 100 persons and they gheraod the officers and the General Manager and Sofa Chairs of the General Manager's Chamber were torn; that the workman was immediately suspended and after the suspension on 3-10-88 the workman organised an illegal agitation and the workman along with the other workmen prevented the General Manager and other officers from leaving the Factory; that similar incident was repeated on 4-10-88; that the management issued the charge-sheet against the workman for gross misconduct and the Enquiry Officer, Shri P. K. Choudhary, after conducting the enquiry issued the show cause notice for the dismissal of service and the services of the workmen were terminated.

3. The workman has not filed the statement of claim. However, on 1-2-1995 the workman appeared and filed an application for the withdrawal of the case; that the workman prayed that the proceedings be dropped as the matter for amicable settlement in being considered by the higher authorities.

4. The workman is not interested in pursuing the terms of the reference regarding the termination of his services. In view of the prayer of the workman to drop the proceedings the case is hereby closed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 670.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जनरल मैनेजर टेलीकाम रेलवे इलेक्ट., नागपुर के प्रबंधन के संबंध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/166/90-आई.आर.(डी.यु.)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 670.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of The General Manager Telecom, Railway Electrification, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-1995.

[No. L-40012/166/90-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(91)/1991.

#### BETWEEN

Shri Ravindra Gajanand Nakshine, Casual Labour, C/o Sulekha Kumbhare, Hardas Nagar, KAMPTEE, Nagpur (MS)-440 001.

#### AND

The General Manager, Telecom Railway Electrification, 300 B. Hennessey Road, Civil Lines, Nagpur (MS)-440 001.

#### PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Workman : None.

For Management : None.

INDUSTRY : Telecom Rly.  
Electrification.

DISTRICT : Nagpur (MS).

#### AWARD

Dated : January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/166/90-IR(DU) dated 19-4-1991 for adjudication of the following industrial disputes:—

#### THE SCHEDULE

“Whether the action of the management of Telecom Rly. Electrification, Nagpur in terminating the services of Shri Ravindra Gajanand Nakshine, Casual Labour is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?”.

2. The case of the management is that the workman was employed in Railway Electrification with effect from 1-7-89 and he left the job without intimation and permission from 18-10-1989 and that the workman inspite of repeated intimation did not report for duty; that the workman left the work voluntarily and as such the workman who was a casual labour was terminated from the service.

3. The workman inspite of repeated notice sent by the Tribunal failed to appear and file the statement of claim.

4. Consequently, the action of the management in terminating the services of the workman is held justified and the reference is answered in favour of the management. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

## AWARD

Dated, January 30, 1995

का.आ. 671.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जनरल मैनेजर, टेलीकॉम रेलवे इलेक्ट्रि., नागपुर के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/168/90-आईआर(डीयू.)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 671.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of G. Manager, Telecom Railway Elect., Civil Lines, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. 40012/168/90-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

## IN THE CENTAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(94)/1991

## BETWEEN

Shri Suresh Sitaram Yadav C/o Miss Sulekha Kumbhare, Hardas Nagar, Kamptee, Nagpur (MS)-440001.

## AND

The General Manager, Telecom Railway Electrification, 300-B, Hennessey Road, Civil Lines, Nagpur (MS)-440001.

## PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

## APPEARANCES :

For workman : None.

For Management : None.

INDUSTRY : Telecom Railway Electrification

DISTRICT : Nagpur (M.S.)

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/168/90 IR(DU) dated 19-4-1991 for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management in terminating the services of Shri Suresh Sitaram Yadav is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. The case of the management is that the workman was engaged with effect from 24-11-87 in Railway Electrification, Nagpur Division and he was orally and verbally informed that his work was not satisfactory and the management finding that no improvement is being made by the workman in his work, issued a letter that his services are no longer required from 10-1-90; that the management gave one month's notice and the compensation to the workman and observed all the formalities required for retrenchment. It is alleged by the management that the workman voluntarily did not propose for work.

3. The workman has not filed the statement of claim in spite of repeated opportunities given to him in last 3 years. Management has retrenched the workman after observing all the required formalities. Consequently, the action of the management in terminating the services of the workman is justified and he is not entitled for any relief.

4. Reference is answered in favour of the management. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY,  
Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 672.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिस्ट. मैनेजर, टेलीफोन भवन, जलगांव के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

संख्या एल-40012/227/91-आई.आर. (डी.यू.)

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी



New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 672.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Distt. Manager, Telephone Bhavan, Jalgaon and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-40012/227/91-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Desk Officer

### ANNEXURE

#### IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR(MP).

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(136)/1992

#### BETWEEN

Shri Dattaram Hari Baykar, represented through the Asst. Circle Secretary, AITEE Union Class-III, Jalgaon (MS)-506167.

#### AND

The Telecom Distt. Manager, Telephone Bhavan, Jalgaon District Jalgaon (MS)-506617.

#### PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Workman : Shri M.S. Choudhary.

For Management : Shri K.T. Choudhari.

INDUSTRY : Telephone DISTRICT : Jalgaon (MS)

#### AWARD

Dated : January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/227/91-IR(DU) dated 25-6-1992 453 GI/95—9

for adjudication of the following industrial dispute :—

#### SCHEDULE

“Whether action of the Telecom District Manager, Jalgaon in terminating the services of Shri Dattaram Hari Baykar is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?”

2. The statement of claim and the written statement was filed by the parties. A joint application was filed by the Union and the Management that the reference has been transferred from Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur to Central Government Industrial Tribunal, Bombay and the Presiding Officer of CGIT, Bombay registered this Ref. as Ref. No. CGIT-1/73 of 1992. It is further alleged by the parties that the reference has been disposed of on 8-12-1993. Copy of the order of the transfer of this reference to CGIT, Bombay is also filed. It is informed by the Secretary, CGIT, Jabalpur that he has not received the order of transfer of this reference. However, in view of the joint prayer of the Union and the Management to drop the reference as the same is already transferred to CGIT Bombay and disposed of, no further proceedings in this reference is called for.

3. In view of the joint prayer of the parties to drop the proceedings as the reference is answered and disposed of by the CGIT, Bombay on 8-12-93, the proceedings are hereby closed. Reference is disposed of accordingly.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 673.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जनरल मैनेजर टैलीकॉम रेलवे इन्डस्ट. नागपुर के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/169/90-आई.आर. (डी.यू.)]

के.वी.वी. उप्प्री, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 673.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation

to the management of G. Manager Telecom Railway Electrification, Civil Lines, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-40012|169|90-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT|LC(R)(93)|1991

#### BETWEEN

Shri Anand Madhorao Indorkar C/o Sulekha Kumbhare, Haydas Nagar Kamptee, Nagpur-440001.

#### AND

The General Manager, Telecom Railway Electrification 300-B, Henessey Road, Civil Lines, Nagpur-440001.

#### PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

#### APPEARANCES :

For Workman : None.

For Management : None.

INDUSTRY : Railway DISTRICT : Nagpur (MS)

#### AWARD

Dated : January 30 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012|169|90 IR(DU) dated 19-4-1991 for adjudication of the following industrial dispute :—

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Telecom Railway Electrification Nagpur in terminating the services of Shri Anand Madhorao Indorkar is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?”

2. The case of the management is that the workman, Shri Anand Madhorao Indorkar was engaged as a Casual Labour on 1-9-87 in Short Term Project of Railway Electrification at Nagpur and as no work was left with the Railway Electrification the workman was disengaged for work from 1-9-1989 and as per requirement one month's notice was given to the workman and compensation for the retrenchment was also paid to him.

The management has prayed that the workman is not entitled for the reinstatement and consequential benefits.

3. The workman failed to file statement of claim inspite of notice sent to him for 29-4-91 1-7-91, 22-8-91, 28-1-92, 6-3-92 and 10-1-95.

4. The management has retrenched the workman after one month's notice and the compensation as no work was left for the workman for which he was engaged as a Casual Worker. Consequently, the reference is answered in favour of the management. No order as to costs

ARVIND KUMAR AWASTHY,  
Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.आ. 674 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिनियर सुप्रेन्डेंट-ऑफ पोस्ट ऑफिस, अमरावती के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 फरवरी, 1995 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-40012/246/91-आई आर(डीयू)]  
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 674.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Senior Supdt. of Post Offices, Amarawati Division, Amarawati Camp, and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-40012|246|91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT|LC(R)(199)|1992

#### BETWEEN

Shri Vijay Anandrao Aware, represented through the President All India Postal Employees Union, Postman and Class IV with EDA, Amaravati Division, Amravati Camp-444602 (Maharashtra).

AND

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

The Senior Supdt. of Post Offices, Amarawati Division, Amarawati Camp-444602 (MS).

PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For workman : Himself.

For management : Shri B.G. Mankar.

INDUSTRY : Postal DISTRICT : Amravati (MS)

AWARD

Dated : January 30 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/246/91-IR(DU) dated 25-9-1992, for adjudication of the following industrial dispute :—

## SCHEDULE

“Whether the action of the management of the Senior Supdt. of Post Offices|Amaravati Division|Amaravati (Maharashtra) in terminating the services of Shri Vijay Anandrao Aware, Extra-Departmental Agent Vishroli branch Office, w.e.f. 9-8-91 if justified ? If not, to what relief he is entitled to ?”

2. Parties filed the settlement and the settlement was verified and accepted. The management has agreed to appoint the workman. Reference is regarding the termination of the services of the workman. The settlement is just and proper. Following are the terms of settlement :—

## TERMS OF SETTLEMENT

1. The workman Shri Aware will be appointed in the vacant post of EDDA Surali BO(Br. Thadi SO) immediately.

2. The applicant will withdraw the I.D. case under reference immediately.

3. The applicant will not claim for the cost of suit and any other expenses.

4. The applicant will not claim for any pay and allowance for the period of 9-8-91 to the date of appointment.

5. His appointment will be fresh and he will not claim for seniority of previous service rendered at Wishroli.

3. In view of the aforesaid settlement no dispute is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY,  
Presiding Officer

का.आ. 675 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिस्ट्री मैनेजर, टेलीफोन भवन, जबलपुर के प्रबन्धन के संबंध में नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-140012/226/91-आई.आर (डी.यू.)]

के.वी.वी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 675.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Dist. Manager, Telephone Bhawan, Jalgaon and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-40012/226/91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(135)/1992

## BETWEEN

Shri Vinod Suryabhan Ingole, represented through the Asstt. Circle Secretary AITEE Union Class-III, Jalgaon-506167.

AND

The Telecom Distt. Manager, Telephone Bhawan, Jalgaon Distt Jalgaon-506167 (MS).

PRESIDED IN :

By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For workman : Shri M. S. Choudhary.

For management : Shri K.T. Choudhary.

INDUSTRY : Telephone DISTRICT : Jalgaon (MS).

AWARD

Dated : January 30, 1995

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification

No. L-40012/226/91-IR(DU) dated 25-6-92 for adjudication of the following industrial dispute :

### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Telecom Distt. Manager, Jalgaon in terminating the services of Shri Vindo Suryabhan Ingale is justified ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. Parties have filed the statement of claim and the written statement. The Presiding Officer retired after the date of hearing in the case on 25-8-1992. The workman filed an application on 28-9-92 that the Ministry of Labour New Delhi vide letter dated 7-10-1992 has transferred this case to Central Government Industrial Tribunal, Bombay. The workman has filed an application on 11-1-95 before me that this reference was transferred to CGIT, Bombay and the same was registered as Ref. No. CGIT-1/72 of 1992 and the matter is disposed of by the Central Government Industrial Tribunal, Bombay.

3. Parties request to drop the proceedings in view of the award by the Central Government Industrial Tribunal, Bombay. Prayer is hereby accepted and this reference in the aforesaid circumstances stands closed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY,  
Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.प्र. 676 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ पोस्ट मास्टर, पटना के प्रबन्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 धनबाद के पंजपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-40012/81/93-आई.आर. (डी.यू.)]  
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 676.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chief Post Master, Patna and their workmen, which was received by the Central Government on 13-2-95.

[No. L-40012/81/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 233 of 1994

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Chief Post Master.

AND

Their Workmen

#### PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

#### APPEARANCES :

For the Employers—None.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Postal.

Dated, the 31st January, 1995

#### AWARD

By Order No. L-40012/81/93-IR(BU) dated 13-10-1994, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of the Postal Service, Bihar Circle, Patna, G.P.O. in terminating the service of Shri Sheo Shankar Sharma, Ex-ED Stamp Vender, Substitute Patna G.P.O., w.e.f. 15-9-90 is proper, legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The order of reference was received in this Tribunal on 20-10-1994. Thereafter, notice was issued to the concerned workman to file written statement on 31-1-1995.

3. On 25-1-1995 a letter was received from Sri Sheo Shankar Sharma, Ex-ED. Stamp Vender and the concerned workman, by post praying to withdraw his case as he has been appointed as E.D. Stamp Vender by the management. A letter was also received from Sri R. V. Ram, Chief Post Master, Patna, G.P.O. stating that appointment of the workman, Sheo Shankar Sharma as substitute E.D. Stamp Vender Patna, G.P.O. in place of Smt. Gavamuni Kumari had already been regularised vide Memo No. E-30/Ch.II. dated 1st October 1993. The Chief Post Master had further requested that the reference may be dropped as now there was no dispute.

4. In view of prayer of both the sides, the date fixed by order dated 15-12-94 was recalled and the reference was placed for order on 25-1-95.

5. From the aforesaid applications of both sides, the dispute having been raised by the workman himself, it appears that now there is no dispute between the parties.

6. Under the circumstances, I render a 'no dispute award in the present reference case.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

का.प्रा. 677 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंखट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/49/92-आई.प्रा. (बी.-2)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th February, 1995

S.O. 677.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 16-2-95.

[No. L-12011/49/92-IR(B.II)]

V. K. SHARMA Desk Officer.

## ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA :

BHUBANESWAR :

Present :

Sri P. K. Tripathy, M.A.L.L.B.,  
Presiding Officer, Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

453 GI/95—10

## INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 7 OF 1993 (CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 30th January, 1995  
Between :

The management of Indian Overseas Bank,  
Bisra Road, Rourkela-11, Dist : Sundergarh.

First party-  
management.

(And)

Their workmen represented through  
Indian Overseas Bank Employees' Union,  
Bisra Road, Rourkela.

Second party-  
workmen.

Appearances :

Sri A. S. R. Murthy, Dy. Chief Officer—For  
the first party-management.

Sri Maheswar Swain, General Secretary of  
the Union.—For the second party-  
workmen.

## AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section(1) and sub-section(2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short the 'Act') have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-12011/49/92-IR (B.II) dtd. 16-2-93 :—

"Whether the action of the management of Indian Overseas Bank, Bisra Road Branch, Rourkela-11, Dist : Sundergarh in not entrusting minor supervisory duties to the senior most award staff in the absence of the Manager is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

2. Undisputed facts available from the pleadings of the parties are that the management bank is a public sector undertaking, service conditions of the workmen staff are governed by various awards and settlements made from time to time and relating to entrustment of "minor supervisory works" the management of Indian Overseas Bank and its workmen represented by All India Overseas Bank Employees' Union, made a settlement on 13-9-90 in presence of the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras in accordance with the provisions in Section 12(3) of the

Act and that the "operational guideline" in the form of a circular letter was circulated by the management on 16-2-91.

3. Further case of the second party/union is that the then Manager of the Rourkela Branch of the Bank was transferred and substitute was posted but the substitute did not immediately reported to duty. Senior official in the branch were assigned with the duties of the Manager and consequentially Sri S. C. Tanty, the senior most Clerk was entrusted with the minor supervisory works and paid special allowance with effect from 25-1-91, as per the provisions in the aforesaid settlement and circular letter. In addition to that the minor supervisory works were entrusted to the next eligible clerical members when some other officer remained absent. But abruptly and unilaterally the management withdrew the benefit of entrustment of minor supervisory works to the eligible clerical staff which has been done in contravention of the provisions in Section 9-A of the Act. Thus, the second party/union has prayed for an award for re-enforcement of the said settlement relating to entrustment of minor supervisory work and for grant of that allowance with 12 per cent interest to the Clerical staffs who would have got that benefit if the practice would not have been stopped with effect from 15-7-91.

4. The first party/management without disputing the fact of transfer of the Manager and order for posting of another officer and non-joining of the later has contended that in the absence of the Manager, other officers officiated and that matter is governed by the service condition of the Officer with which the award staff has no connection. The management has further stated that the then Branch Manager of Rourkela branch was transferred and relieved on 25-1-91. The Officer who was transferred in his place did not join, so he cannot be treated as posted or on the rolls of Rourkela, hence the benefit claimed by the second party/union never accrued in favour of the Award staff of that branch. On 15-7-91 circular was issued by the Management by way of making clarification regarding the manner in which the settlement is to be interpreted and implemented and not with an intention to withdraw any benefit provided in the settlement dated 13-9-90, nor any such benefit to the award staff has been withdrawn vide that circular. The Award staff of Rourkela being not entitled to do any minor supervisory work (during the relevant period) and they being not entrusted with any such minor supervisory work, the second party is not entitled to the reliefs claimed. The management has further stated that the alleged action of the management being within its administrative competency, the dispute raised and the reference made is not maintainable.

5. On the basis of the aforesaid rival contentions

of the parties. the following issues have been framed :—

### ISSUES

1. If the action of the management of Indian Overseas Bank, Birsa Road Branch, Rourkela-11. Dist. Sundergarh in not entrusting minor supervisory duties to the senior most award staff in the absence of the Manager is justified ?
2. If not, to what relief the workmen are entitled to ?
6. At the stage of hearing of the case, both the parties declined to adduce oral evidence. They relied upon documents and did not insist for formal proof hence on admission Exts. 1 and 2 from the side of the second party and Exts. A to E/1 from the side of the management have been marked and accepted in evidence. The details of the relevant exhibits shall be mentioned at relevant places (in this Award).
- Issue No. 11
7. While deciding this issue, the contention of the management regarding maintainability of the proceeding should be decided first. According to the management, the disputed point relates to the internal administrative matter and hence, not an internal dispute. Keeping in view the provisions in Section 2(j) & (ka) and Section 2(s) of the Act, at the stage of argument, the management has not disputed that the award staff, i.e., the Clerical staff of the bank are the 'workmen' and the management-bank is an 'industry' and comes within the purview of 'industrial establishment' as defined in the above-noted sub-section to Section 2 of the Act. The first party-management has also not disputed that there exists relationship of employer and employee between the first party and the award staff. In presence of so much of admitted facts and circumstances, the contention of the management relating to the maintainability of the proceeding is non-sustainable, inasmuch as, the dispute under reference has a direct connection with the conditions of service relating to the terms of employment and the wages as mentioned in Section 2(k) of the Act. Hence, it is held that the dispute is not confined to an internal administrative matter but it is a matter concerning the conditions of terms of employment and condition of labour relating to payment of special allowance, which is a part of the wages. Thus, the reference and the proceeding are both maintainable.

8. While coming to the main matter under reference, it is seen that the parties have not at all adduced any oral evidence and have relied upon only documentary evidence which shall be dealt-with while discussing different contentions of the

parties. At the risk of repetition, it may be stated that the admitted case of both the parties is that the then Branch Manager of Rourkela Branch was transferred and relieved on 25-1-91 and he Officer who was transferred in his place did not at all join. But the contention of the second party that due to such vacancy when the Officers of the Rourkela branch officiated in the post of the Branch Manager, at that time in place of such Officers the minor supervisory work was entrusted to the senior most Clerk Sri S. C. Tanti and also to other senior Clerks as and when required, has not been admitted by the management in their written statement. On the other hand, they have contended that no such minor supervisory work was entrusted due to the aforesaid facts and circumstances. Under such circumstance, it was necessary for the workmen to prove that disputed fact. As has been mentioned above, the workmen have not led any evidence to prove that aspect of the case. Hence, the contention of the second party that Sri S. C. Tanti and other senior Clerks were entrusted with minor supervisory work between 25-1-91 to 15-7-91 is not proved by the workmen.

9. Be that as it may, the reference is still liable to be answered as to whether in such an occasion the minor supervisory work is liable to be entrusted to the eligible award staff. Ext. D is the settlement dated 13-9-90 in which the matter under reference was resolved and resulted in the aforesaid settlement. The relevant portion of the said settlement has been marked as Ext. D1. Out of that, Clause 10(a) and 11 being relevant for the purpose of discussion, those paragraphs are quoted as hereunder :—

**“Clause-10 : BASIS**

- (a) In the event of officers (including Agricultural officers|Field Officers but excluding officers in Scale IV and above|Officers on probation, recruited directly, Veterinary Officers or any specialist officers like Chartered Accountants or Cooperative Officers) proceed on leave, deputation or training for more than ten days. However, when an Agricultural Officer|Field Officer is deputed to other branches minor supervisory duties shall not be entrusted in their absence.

(b) xx            xx            xx            xx  
to

(e) xx            xx            xx            xx

**“Clause 11 :—**

Posted strength of officers in a branch| for the purpose of entrustment shall be the number of officers posted and or on the rolls of the branch excluding officers

on deputation to that branch and including those transferred and substitute not posted for ten days and above. However, minor supervisory duties shall not be entrusted in the vacancies arising on account of officers transferred from branches in metropolitan|urban and semi-urban areas and substitutes not posted irrespective of the duration. Similarly, entrustment of minor supervisory duties shall not arise due to vacancies caused by retirement, death, resignatoin, voluntary retirement, dismissal etc..”

In that connection, the management issued circular dated 16-2-91 which has been marked as Ext. E from the side of the management and Ext. 1 from the side of the workmen. That is an admitted document of both the parties and correctness of that document has not been questioned. In that circular letter instructions have been imparted for interpretation and implementation of the terms of the aforesaid settlement. So far the matter relating to minor supervisory work is concerned, the relevant provisions to which the parties have referred to may be quoted as hereunder :—

**“Clause 2 : BASIS**

- 2.1. Minor supervisory duties shall be entrusted to eligible senior clerical members in the event of Officers proceeding on leave, training or deputation for more than TEN days.

2.2 xx            xx            xx            xx  
to  
2.8 xx            xx            xx            xx

**Claused 3 : Posted Strength and Entrustment :**

- 3.1 Minor supervisory duties shall be entrusted on the basis of posted strength of officers of the branch.

- 3.2 Posted strength of officers in a branch for the purpose of entrustment of Minor supervisory duties shall be the number of officers posted and or on roll of the branch excluding officers on deputation to that branch and manager posted and taking over the charge, till the relief of previous manager.

3.11  
to xx            xx            xx            xx  
3.11

It is appropriate to mention here about the circular dated 15-7-91 (Ext. 2) the correctness of which is under challenge in this reference.

“Attention of branches is invited to Central Officer Circular No. 7(f) of 1990-91 dated 16-2-91 on the above matter.

As a clarification we advise that posting takes effect only when a member is relieved and posted to the branch where he is transferred. There may be occasions where a long time may be taken for a member to be relieved and it does not mean that MSW should be entrusted and the relative special allowance paid for this period also i.e., prior to reporting at the place posted to.

Please be guided accordingly."

10. Referring to the above quoted provisions in the settlement and the circular, the contention of the second party-workmen is that the circular dated 15-7-91 (Ext. 2) is in violation of the terms of the settlement. According to them, when a Branch Manager is transferred and in his place a posting order is passed in favour of another officer, if he does not join then the minor supervisory work should be entrusted to the award staff by holding that such successor has been 'posted'. The contention of the management is that in such a situation the successor having not been joined the word posted is not satisfied and therefore, the minor supervisory works should not be entrusted. Since there were some confusions in respect of interpretation of the term in the settlement and the circular when such a situation was arising, therefore, the management issued the circular, Ext. 2 in the shape of clarification and not with a view to deprive the workers from minor supervisory work.

11. On a reference to the above quoted provisions and without making repetition of the same, it may be noted that the intention of the parties crystal clear that in the event of leave, deputation or training of a particular categories of officers including the duration of absence, that entitles the award staff to be entrusted with minor supervisory works. This is apparent from Clause-10(a) of Ext. D. In that context, while defining the term 'posted strength', in Clause-11 the meaning which has been given to the term 'posted' actually means if an officer is posted i.e. to say joined at the station after being transferred to that post. It does not mean an officer merely under order of transferred but neither relieved nor joined. This interpretation finds support from Clause-3.4 (in Ext. E) which has been quoted above. It may further be mentioned that the workmen have not disputed the correctness of the interpretation made in the circular letter, Ext. E. Rather they have relied upon the same and the above, noted Clause-3.4 clearly mentions that minor supervisory duties should not be entrusted in place of officers transferred and relieved but substitute not posted. Under such circumstances the circular dated 15-7-91 i.e. Ext. 2 does not violate the terms & conditions of the settlement, Ext. D or the terms & conditions enumerated in the circular. Ext. E (which is also Ext.1).

12. The schedule of dispute mentions that whether not entrusting the minor supervisory duties to the senior most award staff in absence of the Manager is justified. As has been discussed above, it has not been disputed by both the parties that the previous manager was transferred on 25-1-91 and thereafter the Officer who was ordered to be transferred and posted as the Manager did not join in Rourkela branch. The same vacancy created cannot be regarded as absence so as to consider the question of entrustment of minor supervisory works in view of the above discussed provisions, both in the Exts. D & E.

13. Hence, award is passed to the effect that no illegally was committed by the management for not entrusting minor supervisory work to the Award staff when the Manager being transferred to Rourkela had not been relieved from his former station and had not joined at Rourkela. Thus, the workmen are not entitled to any relief.

The reference is thus answered accordingly.

Dictated & corrected by me.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

का.प्रा. 678:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओ.एम.डि.सि. लिमिटेड, ओनर भद्रसाहि माईन्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उडिसा भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 16-2-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-27011/3/88-डी 3 (बी)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1995

S.O. 678.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of OMDL Ltd., Owner Bhadrasahi Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 16-2-95.

[No. L-27011/3/88-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer



**ANNEXURE**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA,**  
**BHUBANESHWAR**

**PRESENT :**

Sri P. K. Tripathy, M.A.L.L.B.,  
Presiding Officer, Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 2 of 1989  
(Central)

Dated, Bhubaneswar, the 27th January, 1995

**BETWEEN**

The mangement of OMDC Ltd., Owner  
Bhadrasahi Mines, P.O. Thkurani,  
Dist : Keonjhar.

..First party mangement.

**AND**

Their workmen represented through Barhil  
Mazdoor Sangha Thakurani, Barbil, Keonjhar.

..Second party workmen.

**APPEARANCES :**

None—For both the parties.

**AWARD**

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-27011/3/88-D. III(B) dated 21-12-88:—

“Whether the demand of the Barbil Workers’ Union Bolani, Dist : Keonjhar that the 30 Pickers (as per the list attached to the order of reference) should be paid monthly graded scale of pay i.e. Basic Rs. 190+Food Value Concession Rs. 232+D.A.—Rs. 90.25+Kerosene Oil Allowance Rs. 21.96 at par with the wage rate of monthly paid departmental Pickers, is justified? If so, what relief the workmen and entitled to?”

2. This case had been posted to 23-1-95 for filing written statement by the management. On that date the management, inspite of notice, did not file its written statement. A perusal of the record would reveal that the second party-workmen have already been set exparte on different dates. From the conduct of the parties, it appears that they are no more interested in the ‘lis’. Under such circumstance, this Tribunal has no other option than to

pass a no dispute Award in the case and accordingly a no dispute Award is passed in so far as the present reference is concerned.

Dictated & corrected by me.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995

का.प्र. 679:— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-3-95 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय-5 और 6) धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबन्ध अन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला पश्चिम गोदावरी के मंडल पलकोडेह में राजस्व ग्राम श्रंगवरुक्कम, कोन्डेपुडी, वेन्द्रा अग्रहरम, कुमाडावल्ली, मोगालू, पेनाडा, गोरगनमुडी, वीसाकोडेह, पलकोडेह, और मंडल वीरावमारम में राजस्व ग्राम नोवाडुरु, अन्दलुरु और तेलेरु के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ”।

[संख्या : एम-38013/16/95-एसएस-1]

जे.पी. शुक्ला, भ्रवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1995

S.O. 679.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

“The areas falling within the revenue villages of Srungavruksham, Kndepudi, Vendra Agraharam, Kumadavalli, Mogallu, Pen-nada, Goraganamudi Vissakoderu and Palakoderu in Palakoderu mandal and revenue villages Novuduru, Andaluru and Toleru in Veeravasaram mandal of West Godavari District”.

[No. S-38013/16/95-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995

का.प्रा. 680:—केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि मैग्नेसाइट खनन उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 24 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए,

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छः मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/8/85-डी-1 (ए)]

एस.एस. पराशर, अव्वर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1995

S.O. 680.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Magnesite Mining Industry, which is covered by entry 24 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/8/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

का.प्रा. 681:—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवायें घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/13/85-डी-1 (ए)]

एस.एस. पराशर, अव्वर सचिव

New Delhi, the 21st February, 1995

S.O. 681.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Cement Industry which are covered by entry 3 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purpose of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/13/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1995

का.प्रा. 681:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 2585 दिनांक 12 सितम्बर, 1994 द्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 12 सितम्बर, 1994 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 12 मार्च, 1995 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/3/91-आई.प्रा. (पालिसी विधायी)]

एस. एस. पराशर, अव्वर सचिव

New Delhi, the 23rd February, 1995

S.O. 682.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of

sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India, in the Ministry of Labour S.O. No. 2585 dated 12th September, 1994, the India Security Press, Nasik to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 12th September, 1994;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 12th March, 1995.

[No. S-11017/3/91-IR(PL)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

